पेज 09 में...
तीन दिवसीय सिरपुर महोत्सव शुरू

साप्ताहिक
शहर सत्ता
PRGI NO. CTHIN/25/A2378
सोमवार, 02 फरवरी से 08 फरवरी 2026
हम दिखाएंगे आईना...

पेज 09 में...
राजिम कुंभ कल्प का भव्य शुभारंभ

वर्ष : 01 अंक : 48 पृष्ठ : 12 मूल्य : 5 रुपए www.shaharsatta.com

पेज 04 गरीबों के लिए बनाए फ्लैट्स मेफेयर ने खरीदे

आत्मनिर्भर बजट

ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा बजट 15% बढ़ा

इनकम टैक्स में बदलाव नहीं, करदाताओं को राहत

17 कैंसर मेडिसिन ड्यूटी फ्री, 3 आयुर्वेदिक एम्स

7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे

सीतारमण लोकसभा में तमिलनाडु की प्रसिद्ध कांजीवरम साड़ी पहनकर पहुंचीं जरूर, लेकिन इसी साल होने वाले पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी चुनाव पर सीधा असर डालने वाली घोषणाएं नहीं कीं। बजट भाषण में कोई सीधा चुनावी ऐलान भी नहीं हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट पेश कर दिया। वे संसद में 85 मिनट बोलीं, लेकिन आम आदमी के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। हालांकि टैक्स फाइल करने में सहूलियत, रेलवे प्रोजेक्ट और 3 नए आयुर्वेदिक AIIMS जैसी नई बातें कही हैं। वित्त मंत्री ने जियो-पॉलिटिक्स और चुनौतियों की बात कही और देश का रक्षा बजट ₹6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹7.85 लाख करोड़ कर दिया। यानी कुल डिफेंस बजट में 15.2% की बढ़ोतरी हुई है। डिफेंस बजट की खास बात यह है कि हथियार खरीदी और सेना के आधुनिकीकरण पर पिछले साल के ₹1.80 लाख करोड़ के मुकाबले इस बार ₹2.19 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे। यह पूंजीगत खर्च में सीधे 22% की बढ़ोतरी है।

सात सबसे बड़ी घोषणाएं...

1. इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया। यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
2. 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा। इनमें मुंबई -पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलिगुड़ी।
3. कैंसर की 17 दवाओं पर से आयात शुल्क हटाया। अभी 5% शुल्क लगता था। हीमोफिलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयांभी ड्यूटी फ्री।
4. 3 आयुर्वेदिक AIIMS खोले जाने की घोषणा। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेंगे।
5. 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास के लिए ₹12.2 लाख करोड़ खर्च करने का ऐलान।
6. 15 हजार सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी।
7. करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे। हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा।

मोदी बोले- ये युवा शक्ति का बजट

पीएम मोदी ने आम बजट को युवाओं को बजट बताया है। कहा कि देश में रिफॉर्म एक्सप्रेस चल पड़ी है। ये स्किल, स्केल और सस्टेनेबिलिटी को मजबूत करने का प्रयास है। सबसे बड़ी पूंजी नागरिक, इसी में निवेश किया।

निराशाजनक बजटः राहुल गांधी

विपक्ष ने बजट को निराशाजनक बताया। राहुल गांधी ने कहा, युवाओं के लिए रोजगार वाला बजट नहीं है। मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर गिर रहा है। निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं। घरेलू बचत में भारी गिरावट आ रही है।

CM बोले- बजट सुनहरे भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक दस्तावेज

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह बजट भारत के सुनहरे और विकसित भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। कर्तव्य भवन में बना हुआ यह पहला बजट है, जिसमें देश के समग्र विकास और प्रत्येक नागरिक के कल्याण को ध्यान में रखा गया है।

2047 तक देश को विकसित बनाने वाला बजट- ओपी चौधरी

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने केंद्रीय बजट को लेकर कहा कि, यह बजट देश को 2047 तक विकसित करने के लिए बनाया गया है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री को बधाई देता हूं।

बैज ने कहा- उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही सरकार

PCC चीफ दीपक बैज ने कहा कि अगले ढाई साल में सरकार छत्तीसगढ़ के माइनिंग कॉरिडोर को अपने पसंदीदा उद्योगपतियों को बेचने की तैयारी में है। राज्य में पहले से ही लगातार खनन हो रहा है।

भूपेश बोले- शराब-महंगी..मछली-सस्ती, प्रदेश को कुछ नहीं मिला

कांग्रेस ने केंद्रीय बजट 2026 पर तंज किया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इसे बेहद निराशाजनक बजट है, इसका प्रतिगामी असर दिखायी दे रहा है, शराब महंगी हुई है, मछली सस्ती हुई है, यही नजर आ रहा है।

क्या सस्ता हुआ

कैंसर की दवाएं: 17 प्रमुख कैंसर दवाओं पर सीमा शुल्क पूरी तरह हटा दिया गया है, जिससे इलाज सस्ता होगा।

मोबाइल फोन और टैबलेट: भारत में असेंबल होने वाले फोन और उनके पुर्जों पर ड्यूटी कम की गई है।

विदेशी टूर पैकेज: विदेश यात्रा के पैकेज पर लगने वाला TCS 5-20% से घटाकर मात्र 2% कर दिया गया है।

विदेशी पढ़ाई: विदेश में शिक्षा के लिए भेजे जाने वाले पैसे पर भी TCS दर 5% से घटाकर 2% कर दी गई है।

इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बैटरी: लिथियम-आयन सेल बनाने वाली मशीनों और कच्चे माल पर छूट दी गई है, जिससे EV सस्ते हो सकते हैं।

सोलर पैनल: सोलर ग्लास और संबंधित सामग्री पर शुल्क हटाया गया है।

माइक्रोवेव ओवन: इसके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले विशिष्ट पुर्जों पर आयात शुल्क में राहत दी गई है।

चमड़े और जूते: निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चमड़े के कच्चे माल पर ड्यूटी घटाई गई है, जिससे घरेलू बाजार में भी जूते सस्ते हो सकते हैं।

क्या महंगा हुआ

शराब: आयातित शराब और मादक पेय पदार्थों पर करों में वृद्धि की गई है।

सिगरेट और गुटखा: तंबाकू उत्पादों पर NCCD (National Calamity Contingent Duty) 25% से बढ़ाकर 60% कर दी गई है।

इंपोर्टेड छतरियां : कम कीमत वाली आयातित छतरियों पर अब कम से कम ₹60 प्रति नग का शुल्क लगेगा।

शेयर बाजार में ट्रेडिंग (F&O): फ्यूचर्स (Futures) पर STT 0.02% से बढ़ाकर 0.05% और ऑप्शंस (Options) पर 0.15% कर दिया गया है।

ATM मशीनें: आयातित एटीएम और कैश डिस्पेंसर मशीनों के पुर्जे महंगे होंगे।

कॉफी मेकर: कॉफी रोस्टिंग और वेंडिंग मशीनों पर मिलने वाली छूट हटा दी गई है।

विदेशी घड़ियाँ: लग्जरी और आयातित घड़ियों के दाम बढ़ सकते हैं।

कमर्शियल गैस सिलेंडर: 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में ₹49 की बढ़ोतरी की गई है।

इनकम टैक्स को लेकर ये 4 बदलाव

1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स कानून

केंद्र सरकार ने पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को बदलकर नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाया जाएगा। ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसमें टैक्स रेट्स या स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, इसके जरिए सिर्फ टैक्स रिटर्न फाइल करने करने की प्रोसेस आसान बनाई जाएगी।

विदेश रुपए भेजने पर कम टैक्स

पढ़ाई और इलाज के लिए विदेश पैसे भेजने पर अब कम टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) लगेगा। सरकार ने इसे 5% से घटाकर 2% करने का फैसला किया है। विदेशी टूर पैकेज पर लगने वाले 5% और 20% के TCS रेट को घटाकर 2% किया गया है।

TDS न कटवाने के लिए एप्लिकेशन की जरूरत नहीं

टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) नहीं कटवाने के लिए अलग से एप्लिकेशन देने की जरूरत नहीं होगी। नियमों अनुसार अब अगर आप पर इनकम टैक्स नहीं बनता है तो आपका TDS नहीं काटा जाएगा। अभी इसके लिए फॉर्म 15G (60 साल से कम वालों के लिए) या फॉर्म 15H (वरिष्ठ नागरिकों के लिए) जमा करना होता था।

31 मार्च तक फाइल कर सकेंगे रिवाइज्ड रिटर्न

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में सुधार करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। अब मामूली फीस देकर 31 दिसंबर की जगह 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल किया जा सकेगा।

स्वास्थ्य

कैंसर की दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटेगी, इलाज सस्ता होगा कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। ये एडवांस कैंसर की इंपोर्ट होने वाली दवाएं हैं। अभी 5% कस्टम ड्यूटी लगती थी। हीमोफिलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री कर दी गई हैं।

आयुर्वेद

भारत को ग्लोबल बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी बजट में 3 आयुर्वेदिक एम्स बनाने का ऐलान किया गया है। आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के नेशनल लैब्स बनाई जाएंगी। भारत को ग्लोबल लेवल पर बायोफार्मा प्रोडक्ट के उत्पादन का हब बनाया जाएगा। अगले पांच साल में एक लाख स्पेशलिस्ट हेल्थकेयर प्रोफेशनल तैयार होंगे। इसके लिए ₹10,000 करोड़ के निवेश करने की बात कही गई है।

रेल-जलमार्ग और ग्रीन ट्रांसपोर्ट सेक्टर

7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे शहरों के बीच 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ये मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-चेन्नई, हैदराबाद-बेंगलुरु, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी के बीच बनेंगे। अगले 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनेंगे। बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

हैंडलूम

नेशनल फाइबर स्कीम, खादी को प्रोत्साहन नेशनल हैंडलूम पॉलिसी से कारीगरों को प्रोत्साहन और मदद देने की तैयारी है। मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। मैन मेड फाइबर का उत्पादन बढ़ेगा। एडवांस्ड फाइबर के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का सिस्टम तैयार किया जाएगा। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज मिशन के तहत खादी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोडक्शन, ट्रेनिंग और मार्केटिंग पर जोर होगा।

रक्षा बजट: 15% बढ़ा

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले बजट में सीतारमण ने जियो-पॉलिटिक्स और चुनौतियों की बात कही और देश का रक्षा बजट ₹6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹7.85 लाख करोड़ कर दिया। यानी कुल डिफेंस बजट में 15.2% की बढ़ोतरी हुई है। डिफेंस बजट की खास बात यह है कि इसमें हथियार खरीदी और आधुनिकीकरण पर पिछले साल के ₹1.80 लाख करोड़ के मुकाबले इस साल ₹2.19 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे। यह पूंजीगत खर्च में सीधी 22% की बढ़ोतरी है। विमान और एयरो इंजन डेवलपमेंट के लिए ₹64 हजार करोड़ और नौसेना बेड़े के लिए ₹25 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं। पेंशन के लिए ₹1.71 लाख करोड़ अलग रखे गए हैं।

गर्ल्स एजुकेशन

789 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल, हर जिले में एक हॉस्टल देश में 789 जिले हैं। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने का ऐलान किया गया है। गर्ल स्टूडेंट्स के लिए STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) शिक्षा को विशेष प्राथमिकता देने की बात कही गई है।

महिलाएं

लखपति दीदी मॉडल पर रोजगार और आय बढ़ाने की स्कीम लखपति दीदी की तर्ज पर महिला स्वयं सहायता समूह की उद्यमी महिलाओं के लिए SHE-मार्ट (शी-मार्ट) बनाए जाएंगे। इन दुकानों को महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के समुदाय ही चलाएंगे। यहां महिलाओं के बनाए खाद्य पदार्थ, हस्तशिल्प, कपड़े और स्थानीय उत्पाद सीधे बेचे जाएंगे। इससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और महिलाओं को अपने कारोबार पर मालिकाना हक मिलेगा।

विदेश में पढ़ाई-इलाज

2026-27 में विदेश पैसा भेजने (LRS) पर लगने वाले TCS (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) को कम करने का ऐलान किया है। अब विदेश में पढ़ाई या इलाज के लिए साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा भेजे तो TCS 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है।

खनिज

रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया जाएगा केरल, तमिलनाडु और ओडिशा में दुर्लभ खनिजों के लिए विशेष कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसमें आंध्र प्रदेश को भी जोड़ा जाएगा ताकि खनिज संपन्न राज्यों को फायदा मिले। रेयर अर्थ मटेरियल का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है।

पर्यटन

20 टूरिस्ट प्लेस पर 10 हजार गाइड्स ट्रेंड किए जाएंगे 20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर 10,हजार गाइड्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए पायलट योजना शुरू की जाएगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पर्यावरणीय रूप से ऐसे रास्ते बनाए जाएंगे जो ट्रेकिंग और हाइकिंग के लिए आसान हों।

सीतारमण के 9 बजट, 9 साड़ियां

2019
पहला बजट
साड़ी: मंगलगिरि, आंध्र प्रदेश
खासियत: गुलाबी, सुनहरा बॉर्डर। गुलाबी रंग स्थिरता-गंभीरता का प्रतीक।

2020
दूसरा बजट
साड़ी: रेशम, तमिलनाडु
खासियत: पीली, हरी लाइन वाला किनारा। पीला रंग आनंद-ऊर्जा का प्रतीक।

2021
तीसरा बजट
साड़ी: पोचमपल्ली, तमिलनाडु
खासियत: लाल, ऑफ-व्हाइट। विकास को दिखाने वाला रंग।

2022
चौथा बजट
साड़ी: बोमकाई, ओडिशा
खासियत: भूरा रंग, मरून-सफेद बॉर्डर। शिल्पकारी के प्रति सम्मान दर्शाया।

2023
पांचवां बजट
साड़ी: लाल, काला-सुनहरा बॉर्डर
खासियत: रथ, मोर और कमल के डिजाइन थे। वास्तुकला की विरासत का प्रतीक।

2024
छठवां बजट (अंतरिम बजट- फरवरी)
साड़ी: कांथा, पश्चिम बंगाल
खासियत: बंगाली शिल्पकारों के कौशल को दर्शाया गया।

2024
सातवां बजट (जून)
साड़ी: मंगलागिरी, आंध्र प्रदेश
खासियत: ऑफ व्हाइट, मैजेंटा बॉर्डर, यह साड़ी सादगी के लिए मशहूर है।

2025
आठवां बजट (जुलाई)
साड़ी: साड़ी- मधुबनी, बिहार
खासियत: इसमें मिथिला की पहचान मछली, पानी, कमल, पान और मखाने को उकेरा गया।

2026
नौवां बजट
साड़ी: मैजेंटा कट्टम कांजीवरम सिल्क
खासियत: तमिलनाडु की हाथ से बुनी साड़ी है। हल्के सुनहरे धूरे चेक, यानी कट्टम हैं। सुनहरा ब्रेड वर्क है।

तलवार-डंडे लेकर डकैती की योजना बनाते 6 दबोचे गए

रायपुर। पुलिस ने सिविल लाइंस जैसे पॉश इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में खड़ी स्कार्पियो को घेरकर तलवार-डंडे और हॉकी स्टिक रखे आधा दर्जन युवकों को शुक्रवार को तड़के दबोचा। पता चला कि सभी आरोपी नवापारा-राजिम के निवासी हैं और उनके खिलाफ पहले ही हमले मारपीट जैसे कई मामले दर्ज हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि वे लूट-डकैती की

वारदात करने राजधानी पहुंचे थे। वे शहर के कई हिस्से में गए और सिविल लाइंस में पुलिस की नजर में आ गए। सभी को डकैती जैसे अपराध की योजना बनाने के केस में जेल भेज दिया गया है।

गिरफ्तार आरोपी सी जी 23 जे 6367 नंबर की स्कार्पियो में पकड़े गए। इनके खिलाफ सिविललाइंस पुलिस ने धारा 310(4), 313 बी.एन.एस. एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। जेल भेजे गए आरोपियों में टिकेश शेन्द्रे उर्फ बिल्ला इंदिरा मार्केट वार्ड, आलोक साहनी, कुंदन साहनी, नितेश साहनी तीनों साहनी पारा, शुभम साहनी बढ़ईपारा वार्ड एवं इन्द्र कुमार उर्फ सुमित निषाद दीनदयाल उपाध्याय नगर नवापारा शामिल हैं। ये आरोपी ड्राइवर, स्वीपर आदि का काम करना बताते हैं। आलोक साहनी गोबरा नवापारा थाने का निगरानी बदमाश है और उसके खिलाफ पांच मामले दर्ज हैं।

आधी रात कारों में बैठकर सट्टेबाजी, छह गिरफ्त में, 37.50 लाख कैश बरामद

रायपुर। पुलिस ने गंज थाना क्षेत्र की नागोराव गली में आधी रात दो थार और एसएल सिक्स जैसी महंगी कारें खड़ी करके उसमें बैठकर क्रिकेट सट्टेबाजी कर रहे 6 आरोपियों को दबोचा। इनके कब्जे से 37.50 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। इन आरोपियों की तीन कारें और दस मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत 55 लाख के आसपास बताई गई है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों को गिरफ्तार करके सट्टेबाजों के गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद और टी-20 वर्ल्ड कप के पूर्व एसीसीयू क्राइम ब्रांच की यह पहली बड़ी कार्रवाई है।

म्यूल बैंक एकाउंट और हवाला के भी मिले साक्ष्य

प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसीपी क्राइम स्मृतिक राजनाला, सेंट्रल जोन डीसीपी उमेश प्रसाद गुप्ता एवं अन्य अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार गिरोह ऑनलाइन बैटिंग वेबसाइट से मोबाइल फोन के जरिये सट्टेबाजी करा रहा था। शुक्र-शनिवार की रात साढ़े 12 बजे पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला एवं अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अमित तुकाराम कांबले के निर्देशन व मार्गदर्शन में पुलिस ने कार्रवाई की। इनकी जेएमडीबेट 777 डॉट काम और क्लासिक 777 डॉट काम बैटिंग वेबसाइट के तार महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश व अन्य राज्यों से जुड़े होने के संकेत मिले हैं। इस गैंग से जुड़कर सट्टेबाजी करने और कराने वाले अन्य लोगों के बारे में जानकारी मिली है, जिन पर तकनीकी जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। जब्त नगदी रकम के संबंध में म्यूल बैंक खातों एवं हवाला ट्रांजेक्शन के साक्ष्य प्राप्त हुये हैं। उस संबंध में भी फायनेंशियल इन्वेस्टिगेशन कर कार्रवाई होगी।

चार आरोपी पहले भी जा चुके जेल, लगी गैंगबाजी की धारा

गिरफ्तार आरोपियों में राखबदेव पाहुजा सिविक सेंटर भिलाई, दीपक अग्रवाल आसमा सिटी होम्स सकरी बिलासपुर, पीयूष जैन एनडीआर अपार्टमेंट आलोक विहार रोहिणीपुरम, जितेन्द्र कुमार कृपलानी उर्फ जित्तू इंद्रप्रस्थ कॉलोनी मस्जिद के पास डीडी नगर रायपुर, कमल राघवानी गायत्री नगर 21 बंगलो कॉलोनी खम्हारडीह एवं सचिन जैन हनुमान मंदिर रोड गुढ़ियारी शामिल हैं। इनमें राखब देव, जितेन्द्र कुमार कृपलानी, दीपक अग्रवाल एवं सचिन जैन पूर्व में भी जुआ-सट्टा के केस में गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड दीपक अग्रवाल का मिला है। इनके कब्जे से 37.50 लाख कैश, कार व बरामद मोबाइल फोन की कुल कीमत 92.50 लाख होगी। इनके खिलाफ गंज थाने में धारा 7 के साथ ही संगठित अपराध की धारा 112 (2) बी.एन.एस. के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों ने जिन्हें सट्टेबाजी के लिए रकम लेकर पैनल आईडी बेची है, उन पर भी कार्रवाई होगी।

पुलिस जांच के बीच दुकान-घरों में चोरी

तेलीबांधा और डीडी नगर में सूने मकानों के टूटे ताले

रायपुर। पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद राजधानी में पुलिस एक्टिव मोड में है। इसके बाद भी शहर में चोरी थम नहीं रही है। हर दिन बाइक और मोपेड पार हो रहे हैं। अब तेलीबांधा और डीडीनगर थाना क्षेत्र में दो घरों में चोरी की रिपोर्ट हुई है। इसी तरह जयस्तंभ चौक के पास आदित्य होटल के सामने की गली में स्थित एक ऑटो पार्ट्स शॉप में छत में छेद करके घुसा चोर गल्ले से 13 हजार कैश लेकर फरार हो गया। इन चोरियों के बाद पुलिस ने फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम के साथ मौदहापारा में जांच की। सीसीटीवी फुटेज भी देखे जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि जयस्तंभ चौक में तकरीबन हर दिन पुलिस नाकेबंदी करके देर रात तक वाहनों और संदिग्ध लोगों की जांच-पड़ताल कर रही है। शहर की बस्तियों, कॉलोनियों में भी सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है।

सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ नकाबपोश

पुलिस के मुताबिक मौदहापारा थाने के सामने की गली में स्थित जय ऑटो मोबाइल्स नामक शॉप में चोरी की खबर शनिवार सुबह पहुंची। पीछे की दुकान की ऑटोमोबाइल में घुसा। सीसीटीवी कैमरे में एक नकाबपोश चोर कैद हुआ है। चोर गल्ला तोड़कर 12-13 हजार रुपए नकद ले गया है। एडिशनल डीसीपी तारकेश्वर पटेल, एसीपी कोतवाली दीपक मिश्रा ने टीआई मौदहापारा मुकेश शर्मा के साथ खुद घटनास्थल का निरीक्षण किया और दिशा निर्देश दिए। चोर को लोकल मानकर पुलिस जांच कर रही है। छत पर छेद करके एक चोर जय

सूने मकानों में ताले तोड़कर घुसे चोर

तेलीबांधा थाने में सुमन कौशिक नामक एक गृहिणी ने कांशीराम नगर स्थित अपने सूने मकान में ताला तोड़कर सोने का हार, दो झुमका, दो ईयर रिंग, टॉप्स, एक अंगूठी, चांदी के छह पायल समेत अन्य जेवर चोरी होने की रिपोर्ट लिखाई है। गृहिणी बच्चों के साथ मायके गई थी। जबकि पति मणिशंकर कौशिक घर में रहकर नौकरी करते रहे हैं। 28 जनवरी को पति बिलासपुर गए और फिर परिवार के लोगों के साथ 30 जनवरी को लौटे, तब घर में चोरी का पता चला।

इस बार 20 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं

बोर्ड परीक्षाः 12वीं में विद्यार्थी बढ़े तो 10वीं में घट गए

रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) द्वारा संचालित 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा के लिए इस बार प्रदेश के 5,46,430 विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं। 12वीं में विद्यार्थी पिछले साल से बढ़ गए हैं जबकि 10वीं में विद्यार्थियों की संख्या घट गई है। रायपुर जिले से दोनों कक्षाओं में सबसे ज्यादा विद्यार्थी सम्मिलित होंगे। परीक्षा के लिए 2510 केन्द्र बनाए गए हैं।

परीक्षाएं इस बार 20 फरवरी से प्रारंभ होंगी। पूर्व वर्षों में परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होती आई हैं लेकिन इस बार सप्ताहभर पहले ही परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। माशिमं बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में जोर-शोर से जुटा हुआ है। शीघ्र ही परीक्षा सामग्रियों का वितरण किया जाएगा। 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा के लिए इस वर्ष प्रदेश से 5,46,430 विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं। इनमें प्राइवेट वाले विद्यार्थी भी शामिल हैं। हालांकि पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या पिछले साल से 22,708 विद्यार्थी कम हैं। कक्षा 12वीं में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या गत वर्ष से ज्यादा है जबकि 10वीं में विद्यार्थी घट गए हैं। कक्षा 10वीं में 6839 स्कूलों से 3,21,571 विद्यार्थियों का पंजीयन हुआ है। इसके लिए 2510 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। पिछले साल 3,28,716 विद्यार्थी पंजीकृत हुए थे। इसी तरह कक्षा 12वीं में 4231 स्कूलों से 2,45,859 विद्यार्थियों का पंजीयन हुआ है। पिछले साल पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या 2,40,422 थी। 12वीं की परीक्षा के लिए 2396 केन्द्र प्रदेशभर में बनाए गए हैं।

रायपुर जिले से सबसे ज्यादा विद्यार्थी पंजीकृत

जिलेवार पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या के मामले में रायपुर जिला पहले क्रम पर है। रायपुर जिले से कक्षा 10वीं में 27,544 तथा बारहवीं में 21,473 विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं। इसी तरह बिलासपुर में 10वीं में 22,447 एवं 12वीं में 15,304, दुर्ग में 10वीं में 16,738 तथा 12वीं में 13,563 और बलौदाबाजार में दसवीं में 16,245 तथा बारहवीं में 11,466 विद्यार्थियों का पंजीयन हुआ है।

डॉ, रेशमा अंसारी की पुस्तक का विमोचन रायपुर साहित्य उत्सव मे दिनांक 25,01,2026 को हुआ। डॉ रेशमा अंसारी ने अब तक तकरीबन 13 पुस्तकें लिखकर हिन्दी साहित्य में बड़ा योगदान दिया है। फोटो के दाएं तरफ पति शेख आबिद एवं बाईं ओर उनके छोटे पुत्र रज़ा परिलक्षित हो रहे हैं। डॉ. रेशमा अंसारी वर्तमान में मैट्स यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता विभाग की विभागाध्यक्ष हैं।

काम पहले, टेंडर बाद में, अधीक्षण यंत्री को आरोप पत्र हुआ जारी

रायपुर। पावर कंपनी में बिजली से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए निकाले जा रहे टेंडर में गोलमाल की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने टेंडर प्रक्रिया में बदलाव का खेल लंबे समय से चल रहा है। हालत यह है कि काम पहले कराया जा रहा है और टेंडर बाद में निकल रहा है। राजधानी में टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के बाद एक और अधीक्षण यंत्री को आरोप पत्र जारी किया गया है। पावर कंपनी में सब स्टेशनों के रखरखाव से लेकर बिजली पोल लगाने और ट्रांसफॉर्मर की क्षमता बढ़ाने से जुड़े टेंडर में भर्राशाही चल रही है। चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने टेंडर प्रक्रिया के नियमों को ही दरकिनार किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में राजधानी में भी टेंडर में गोलमाल का खेल चल रहा है।

गड़बड़ी के चलते ही संबंधित अधिकारियों को नोटिस और आरोप पत्र भी जारी हो रहे हैं। ताजा मामला ट्रांसफॉर्मर की क्षमता बढ़ाने का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर संभाग मध्य के अंतर्गत बूढ़ापारा जोन क्षेत्र में आशीर्वाद भवन के स्वीकृत भार 16 किवाँ से 23 किवों बढ़ाने हेतु 63 केवीए ट्रांसफॉर्मर क्षमता

को 100 केवीए किए जाने के कार्य के लिए टेंडर निकाला गया था। बाद में पता चला कि क्षमता वृद्धि का काम टेंडर जारी होने के पहले ही हो चुका है। मामले की जांच में यह तथ्य पाए गए कि नगर वृत्त एक के वर्तमान अधीक्षण यंत्री एम. विश्वकर्मा के निर्देश पर नगर निर्माण संभाग रायपुर द्वारा पहले ही कार्य कराया जा चुका था। इसके लिए कंपनी प्रबंधन ने अधीक्षण यंत्री को जिम्मेदार माना है। बताते हैं कि आरोप पत्र का जवाब दे दिया गया है। जिसमें उन्होंने कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व का कार्य बताते हुए जानकारी नहीं होने की बात कही है। इसको लेकर यह भी सवाल उठ रहा है कि आखिरकार टेंडर जारी करने के पहले अधीक्षण कार्यालय द्वारा जानकारी क्यों नहीं जुटाई गई।

नवा रायपुर में गरीबों के लिए बनाए सवा सौ फ्लैट्स मेफेयर ने खरीदे !

हाउसिंग बोर्ड ने नवा रायपुर सेक्टर-16 में निर्मित दो ब्लॉक को 16 करोड़ रुपए में बेचा

रायपुर। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की विभिन्न आवासीय योजनाओं के अंतर्गत बनाए गए अविक्रित ईडब्ल्यूएस व एलआईजी भवन व फ्लैट्स अब बल्क में बिकने लगे हैं। नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 16 में प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत निर्मित एलआईजी फ्लैट्स भवनों में से पूरे 2 ब्लॉक को मेफेयर समूह ने बल्क में खरीदा है। गृह निर्माण मंडल ने ब्लॉक 36 व 38 में कुल 128 एलआईजी फ्लैट्स को लगभग 16 करोड़ रुपए में बेचा है। प्रत्येक एलआईजी फ्लैट की कीमत 12.66 लाख रुपए बताई गई है। बताया गया है कि राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य प्रवर्तित दीनदयाल आवास योजना, अटल आवास योजना, अटल विहार योजना व नवा रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत पूर्व में जारी नियम व शर्तों में पात्रता के लिए अतिरिक्त प्रावधानों का समावेश कर विक्रय की अनुमति है।

पिछले साल बिकीं 4689 संपत्ति

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने पिछले साल 2025 में 4689 संपत्तियों का विक्रय किया है, जिसका मूल्य 1022 करोड़ रुपए है। मंडल ने कुल आवासों में से 70 प्रतिशत आवास कमजोर व निम्न आय वर्ग के लिए बनाए हैं। शासन द्वारा स्वीकृत वन टाइम सेटलमेंट योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को 30 प्रतिशत तक की छूट दी गई। इसके तहत 220 करोड़ मूल्य की 1452 संपत्तियों का विक्रय किया गया। इसके तहत ही मेफेयर संस्था को नवा रायपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना/ मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित फ्लैट्स में से 126 फ्लैट्स को बल्क में विक्रय किया गया है। हालांकि मेफेयर को शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान की पात्रता नहीं होगी। सेक्टर-16 में निर्मित एलआईजी फ्लैट्स बड़ी संख्या में बिक चुके हैं। यहां अभी भी 400 से अधिक फ्लैट्स रिक्त हैं। रिक्त फ्लैटों के विक्रय के लिए गृह निर्माण मंडल द्वारा फरवरी माह में बुकिंग शुरू की जाएगी। इसी तरह सेक्टर 34 में भी फ्लैट्स बल्क में बेचे गए हैं। इसके अलावा नवा रायपुर सेक्टर-27 में अविक्रित शॉप/हॉल को बेचा गया है।

राज्य शासन के निर्णय के अनुसार ईडब्ल्यूएस एलआईजी भवनों, फ्लैटों के विक्रय के लिए 3 बार विज्ञापन के बाद अविक्रित भवनों को एकल व्यक्ति या शासकीय/अर्धशासकीय अथवा निजी संस्थाओं के नाम पर बल्क में विक्रय किया जा सकता है, परंतु इन्हें शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान की पात्रता नहीं होगी। ईडब्ल्यूएस व एलआईजी भवनों, फ्लैटों के विक्रय के लिए 3 बार विज्ञापन होने के बाद अविक्रित भवनों को, पात्र हितग्राही के अलावा किसी भी आय वर्ग के हितग्राही को विक्रय किए जाने की भी छूट दी गई है। अनुदान की पात्रता केवल निर्धारित आय वर्ग के हितग्राही को ही होगी।

अविक्रित में तेजी संपत्तियों की बिक्री में आई तेजी

राज्य शासन की मंशा के अनुरूप गृह निर्माण मंडल द्वारा प्रदेश में विभिन्न आवासीय योजनाओं के तहत कमजोर व निम्न आय वर्ग के लिए किफायती आवास बनाए जा रहे हैं। वहीं, शासन की छूट के बाद मंडल की अविक्रित संपत्तियों की बिक्री में तेजी आई है।

- अनुराग सिंहदेव, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल

शराब दुकानों के संचालन को लेकर तीन साल के लिए 300 करोड़ का टेंडर जारी

रायपुर। प्रदेश के आबकारी विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीजीएमसीएल) ने शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य की सरकारी देशी, विदेशी व प्रीमियम शराब दुकानों के संचालन के लिए मैन पावर (मानव संसाधन) उपलब्ध कराने के लिए टेंडर जारी किया है। इस बार सीजीएमसीएल ने 3 साल के लिए यह टेंडर जारी किया है। टेंडर भरने की अंतिम तिथि 19 मार्च 2026 है। इसी दिन टेंडर खोला जाएगा। इसके पहले 26 फरवरी को प्री-बिड मीटिंग आहूत की गई है। मैन पावर सप्लाई का टेंडर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए के मुताबिक तीन साल के लिए करीब 300 करोड़ रुपए का है। यहां हैरान करने वाली बात यह है कि इस बार के टेंडर में अनुभव से ज्यादा टर्नओव्हर पर जोर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य में देशी, विदेशी व प्रीमियम शराब दुकानों की संख्या 676 है। नए वित्तीय वर्ष में 67 दुकानें और खोले जाने का निर्णय लिया गया है। आने वाले समय में दुकानों की संख्या 700 के करीब पहुंच जाएंगी। इन दुकानों के संचालन के लिए कम से कम चार हजार कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है। चूंकि दुकानों का संचालन राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम (सीजीएमसीएल) द्वारा किया जाता है, लिहाजा मैन पावर की उपलब्धता टेंडर के द्वारा होती है। गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में दो सालों के लिए मैन पावर सप्लाई का टेंडर जारी हुआ था। इस दौरान मैन पावर सप्लाई टेंडर में अनुभव को प्राथमिकता दी गई थी और टर्नओव्हर भी कुल टेंडर का 30 प्रतिशत रखा गया था, जो नियमानुसार था।

कुछ शर्तों को लेकर हैरानी भी

आबकारी सूत्रों का कहना है कि पिछले मैन पावर सप्लाई टेंडर और वर्तमान में जारी मैन पावर सप्लाई टेंडर में कई तरह की त्रुटियां नजर आ रहीं हैं। पिछली बार मैन पावर टेंडर में ईपीएफ जमा करने वाले रजिस्टर्ड कर्मचारियों के अनुसार ही अंक दिए गए थे, लेकिन इस बार के टेंडर में इस शर्त को ही हटा दिया गया है। जिसे लेकर अभी से सवाल उठने लगे हैं, जिसके आने वाले दिनों में एक बड़ी समस्याएं बनने की आशंका जताई जा रही है। आबकारी सूत्रों का कहना है कि मैन पावर सप्लाई के टेंडर का निर्णय कैबिनेट में नहीं हुआ है। कमेटी ने टर्नओव्हर भी 300 करोड़ रखा है, जो भारत सरकार के सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के नियमों के विपरीत है इसलिए इस टेंडर और सार्वजनिक उपक्रम में भविष्य में सीवीसी की विपरीत नजर पड़ने की संभावना भी है।

रायपुर, दुर्ग-भिलाई में कॉलोनी या उद्योग के लिए एससीआर से मंजूरी जरूरी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर, नवा रायपुर व दुर्ग-भिलाई को मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) विकसित करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में संचालक मंडल के गठन बाद अब छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) की पदस्थापना के लिए प्रस्ताव आवास विभाग ने मुख्य सचिव को भेजा है। वहीं, बताया गया है कि नवा रायपुर, रायपुर, दुर्ग-भिलाई में कॉलोनी निर्माण व उद्योग लगाने के लिए अब एससीआर की मंजूरी लेनी होगी। एससीआर का क्षेत्र अधिसूचित किए जाने बाद कई अधोसंरचना विकास से संबंधित गतिविधियों में तेजी आएगी। साथ ही एससीआर अधिसूचित क्षेत्र में जमीन की खरीदी-बिक्री पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। गौरतलब है कि नए प्राधिकरण के सेटअप के लिए 210 पदों के सृजन को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। एससीआर का मुख्यालय नवा रायपुर में रहेगा। सीईओ की पदस्थापना के बाद संचालक मंडल की पहली बैठक में कई अहम् निर्णय लिए जाने की संभावना है। आवास व पर्यावरण विभाग द्वारा एजेंडा तैयार है। इसमें एससीआर एरिया निर्धारण व सर्वे के लिए कंसल्टेंसी तथा नवा रायपुर-रायपुर-दुर्ग भिलाई मेट्रो रेल परियोजना के डीपीआर के लिए सलाहकार संस्था का चयन आदि शामिल है।

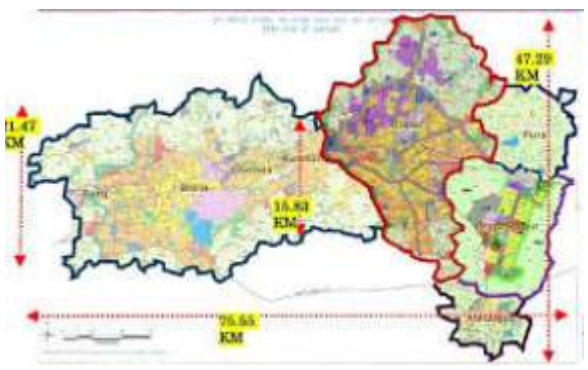

एससीआर में 6000 वर्ग किमी क्षेत्र

एससीआर में रायपुर, नवा रायपुर व भिलाई-दुर्ग सहित आसपास का लगभग 6000 वर्ग किमी क्षेत्र शामिल होगा। एससीआर में वर्ष 2031 तक 50 लाख की आबादी अनुमानित है। इसके अनुरूप एससीआर का इकोनॉमिक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। नवा रायपुर-रायपुर-भिलाई-दुर्ग मेट्रो परियोजना के लिए डीपीआर बनाने की प्रक्रिया चल रही है। टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी अध्ययन के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया है।

जांच में साजिश की पुष्टि नहीं, मान्यता, आरटीई, स्थापना के पुराने दस्तावेज जले

डीईओ दफ्तर की आगजनी में 14 लाख का नुकसान, दर्जनों दस्तावेज खाक

रायपुर। जिला शिक्षा कार्यालय के पुराने भवन में लगी आग की विभागीय स्तर पर की गई जांच की रिपोर्ट कमेटी ने सौंप दी है। आगजनी से शिक्षा विभाग को 14 लाख रुपए से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ है। जांच में किसी तरह की साजिश की पुष्टि नहीं हुई है। आग से मान्यता, आरटीई, स्थापना के साथ ही मदरसा से जुड़े हुए पुराने सारे दस्तावेज जलकर राख हो गए।

17 जनवरी की रात को पेंशनबाड़ा स्थित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पुराने भवन में आग लग गई थी। आग इतनी भीषण थी कि सारे दस्तावेज और आलमारियां जलकर राख हो गई। आगजनी के बाद पुराने भवन को ढहा दिया गया। इस दुर्घटना की जांच के लिए लोक शिक्षण संचालक ने रायपुर संभागीय संयुक्त संचालक संजीव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की थी। कमेटी में लोक शिक्षण संचालनालय के सहायक संचालक बजरंग प्रजापति तथा सतीश नायर सदस्य बनाए गए थे। कमेटी को 5 दिनों के भीतर रिपोर्ट देनी थी किन्तु 10 दिन बाद लोक शिक्षण संचालक को जांच रिपोर्ट सौंप दी गई। कमेटी ने जांच के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बयान लिए। खासकर मान्यता, आरटीई, स्थापना, मदरसा व वित्त शाखा देखने वाले कर्मचारियों से बारिकी से पूछताछ की गई। कार्यालय की ओर से आग से हुए नुकसान की लिस्ट भी जांच कमेटी को दी गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जांच में इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि आग साजिश के तहत लगाई गई है। हालांकि आगजनी रोकने के लिए किए जाने वाले पुख्ता सुरक्षा उपायों में उदासीनता की बात कही गई है। आगजनी से 14 लाख रुपए से अधिक के आर्थिक नुकसान का आकलन किया गया है। आगजनी से मान्यता, आरटीई, स्थापना तथा मदरसा से संबंधित सारे पुराने दस्तावेज जलकर राख हो गए हैं।

आग में ये दस्तावेज जलकर खाक

- विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति से संबंधित दस्तावेज 2 आलमारी में
- मध्यान्ह भोजन से संबंधित दस्तावेज 3 आलमारी में
- भंडार कक्ष के दस्तावेज एवं स्टॉक पंजी 3 आलमारी में
- अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज 3 आलमारी एवं 45 बस्ता
- स्थापना से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज 4 आलमारी और 80 बस्ता
- मान्यता के दस्तावेज 1 आलमारी एवं 25 बस्ता
- इंस्पायर अवार्ड से जुड़े दस्तावेज-1 आलमारी
- विधि कक्ष के विभिन्न प्रकरणों की जांच के दस्तावेज- 2 आलमारी
- वित्त, बजट, अनुदान, मदरसा के दस्तावेज के साथ कम्प्यूटर, लैपटॉप, टेबल, कुर्सी, आलमारी सहित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज व अभिलेख।

संपादकीय

• सुकांत राजपूत

मूंह में राम बगल में नाथूराम

बिलासपुर में अखिल भारतीय हिंदू शौर्य कवि सम्मेलन में "गैर-हिंदुओं की एंट्री बैन" अनाउंसमेंट ने एक दफे फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर ऐसों को लगता है कि मुस्लिम गलत कर रहा है तो हम भी गलत करेंगे...अगर मुस्लिमों को कॉपी करना है तो मोहम्मद रफी को हम क्यों नहीं कॉपी करते या शहीद अब्दुल हमीद को क्यों नहीं कॉपी करते! आरोप है कि अनाउंसमेंट में यह कहा जा रहा है कि "कार्यक्रम में गैर-हिंदू का प्रवेश वर्जित है",इस बयान के सामने आने के बाद शहर के कई सामाजिक संगठनों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए इसे भेदभावपूर्ण और संविधान की भावना के विपरीत बताया है।

सामाजिक संगठनों ने न सिर्फ अनाउंसमेंट की भाषा पर सवाल उठाए हैं,बल्कि पुलिस ग्राउंड जैसे शासकीय स्थल पर इस तरह के आयोजन की अनुमति दिए जाने पर भी आपत्ति जताई है,उनका कहना है कि सार्वजनिक स्थान पर किसी भी समुदाय के प्रवेश पर रोक लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। इस कार्यक्रम को लेकर रवीश कुमार ने भी एक्स पर री-ट्वीट किया है और मज़ाकिया लहजे में कहा कि क्या इस कार्यक्रम को अमरीकी राष्ट्रपति ट्रम्प को भी सुनाया जाएगा। गांधी और हनुमान दोनों के पास राम नाम की ताकत थी इतना इन साइकोपैथ टाइप लोगों को समझना चाहिए। लेकिन ये तो गांधी जैसे राम भक्त की पुण्यतिथि में शराब बेच सकते हैं तो मांस बिक्री भी कर ही देना चाहिए।

आज गांधी फिर याद किए जाएंगे। यह बात तो उनके आलोचक भी मानते हैं कि गांधी जी इंसानियत के शिक्षक थे। और भक्तों का कहना है कि हनुमान जी मानवता के गुरु हैं। गांधी कहा करते थे कि जो सत्य की खोज में हो, वो हिंसक नहीं हो सकता। जब हम सुंदरकांड में हनुमान जी की लंका यात्रा देखते हैं तो इसका प्रमाण मिल जाता है। कुछ बातें गांधी की आज भी सही लगती हैं- सत्यता, सादगी, सदाचार, स्वदेशी और स्वच्छता। गांधी से जुड़ने के लिए सारे रास्ते राजनीति की भेंट चढ़ गए। हनुमान जी और गांधी- दोनों ने भक्ति का सक्रिय रूप समाज को अर्पित किया था। दोनों के पास राम नाम की ताकत थी। हम इसे अपना सकते हैं। लेकिन अपनी रक्त पिपासा के लिए मुंह में राम और बगल में नाथूराम का नाम जपने वाले समाज को दो फाड़ करने में लगे हैं।

सुशील भोले

कोंदा-भैरा के गोठ

-तुँहर बनवाय मूर्ति अउ हमर बनवाय मूर्ति के नॉव म अभी जबर तीरिक-तीरा होवत हे जी भैरा.

-कइसे गढ़न के जी संगी कोंदा?

-कांग्रेस के शासन काल म भगवान राम के ऊँच पूर बड़का वाले मूर्ति ल चंदखुरी के कौशल्या धाम म लगवाए गे रिहिसे ना.. वोकर जगा अभी के सरकार ह आने मूर्ति लगवाय के तइयारी करत हे.

-अच्छा.. भगवान के मूर्ति ल गा!

-हव.. अभी वाले मन के मानना हे- चंदखुरी म अभी जेन राम के मूर्ति लगे हे ते ह राम बरोबर नइ दिखय एकरे सेती वो मन जबलपुर ले एक आने मूर्ति बनवाय हे, जेला वो जगा लगवाए जाही.

-त अतेक दिन ले उहाँ जेन मूर्ति लगे हे तेला कइसे करहीं जी संगी?

-इही बात के तो झगरा चलत हे.. भई मूर्ति ह कोनो किसम ले टूट-फूट जाय रहितीस त तब तो वोला सम्मानजनक ढंग ले विसर्जित कर दिए जातीस, फेर वो मूर्ति ह तो एकदम सही सलामत हे.

-राजनीति वाले मन के अइसने गोठ-चाल ह समझ म आए ले नइ धरय संगी.. तरुवा ह धमके असन करथे.

पार्टी, सरकार, संघ का नया मॉडल

नीरजा चौधरी

भाजपा के नए अध्यक्ष नितिन नबीन की उम्र लगभग उतनी ही है, जितनी कि स्वयं पार्टी की। प्रधानमंत्री ने इस बात को छिपाया नहीं है कि पार्टी की मंशा युवा पीढ़ी पर ध्यान केंद्रित करने और उसका समर्थन हासिल करने की है। नबीन को चुनकर भाजपा नेतृत्व ने गियर बदला है। पार्टी अब संगठन के भीतर से उभरे कार्यकर्ताओं को महत्व देने की ओर लौटती दिख रही है।

एक व्यवस्था स्थापित कर दी गई है। नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा ही प्रदान किया जाएगा और पार्टी अमित शाह की निगरानी में काम करती रहेगी। वहीं नबीन पार्टी-सरकार-संघ के कामकाज के एक नए मॉडल का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें उन राज्यों में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां पार्टी अभी कमजोर है और जहां 2026 और 2027 में चुनाव होने हैं।

देखें तो नितिन नबीन का उदय सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, जहां भाजपा उपयुक्त समय आने पर सरकार का नेतृत्व करने की उम्मीद कर रही है। उनकी जाति (कायस्थ) भी ऊंची जातियों को आश्वस्त करती है, जो ओबीसी और दलितों के पक्ष में भाजपा द्वारा अपनाई जा रही पहचान-आधारित राजनीति से असंतुष्ट हैं।

नबीन की पदोन्नति केवल पार्टी कार्यकर्ता को महत्व देने तक ही सीमित नहीं है, ताकि जमीनी कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा किया जा सके। भाजपा अब ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है, जब वह देश के पूर्व और दक्षिण दोनों हिस्सों में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पार्टी को ऐसे ऊर्जावान नेतृत्व की जरूरत है, जो उसके संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर सके।

वर्षों से पार्टी की कमान राष्ट्रीय कद के दिग्गजों के हाथों में रही है। इसकी शुरुआत 1980 में भाजपा के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी से हुई थी। वाजपेयी ने नई पार्टी के मंत्र के रूप में गांधीवादी समाजवाद को सामने रखा था, ताकि उसे मध्यपंथी दिशा में ले जाया जा सके। यह दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित पार्टी के वैचारिक आधार से अलग था। वाजपेयी और आडवाणी ने पुराने जनसंघ को पुनर्जीवित करने का विकल्प नहीं चुना, जिसने आपातकाल के बाद 1977 के चुनावों में इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने वाली जनता पार्टी में अपनी पहचान विलीन कर दी थी।

1984 में लोकसभा में भाजपा के मात्र दो सीटों पर सिमट जाने के बाद वाजपेयी ने 1986 में आडवाणी के लिए रास्ता छोड़ दिया। पार्टी में आडवाणी युग की शुरुआत हुई और वे तीन बार अध्यक्ष बने। उनके बाद मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, जना कृष्णमूर्ति, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने पार्टी की कमान संभाली।

2019 में अमित शाह अध्यक्ष बने, जिनके नेतृत्व में पार्टी का

अभूतपूर्व विस्तार हुआ। उनके बाद अध्यक्ष बने जेपी नड्डा को पार्टी के लिए भाग्यशाली माना गया। हालांकि उनका कार्यकाल 2023 में समाप्त हो गया था, लेकिन 2024 के आम चुनावों तक उन्हें विस्तार दिया गया। चुनावों के बाद पार्टी नेतृत्व और संघ नेतृत्व के बीच इस बात पर सहमति नहीं बन पाई कि पार्टी की कमान किसे सौंपी जाए। कई नामों पर चर्चा हुई। लेकिन बताया जाता है कि दिसंबर 2025 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अमित शाह और मोहन भागवत की मुलाकात के बाद नबीन के नाम पर अंतिम मुहर लगी।

संघ हमेशा से संगठन को प्राथमिकता देने का पक्षधर रहा है और उससे गहराई से जुड़े नबीन पुराने ढर्रे के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने चार विधानसभा चुनाव जीते हैं, जिससे उन्हें जन-राजनीति की गतिशीलता की समझ है। साथ ही वे संगठन के 'नट-बोल्ट' संभालने वाले व्यक्ति भी रहे हैं। हालांकि, नीतीश सरकार में मंत्री रहने के बावजूद वे ऐसा चेहरा नहीं थे, जो बिहार से बाहर व्यापक रूप से पहचाना जाता हो।

नबीन को चुनकर पार्टी अब संगठन के भीतर से उभरे कार्यकर्ताओं को महत्व देने की ओर लौटती दिख रही है। एक व्यवस्था स्थापित कर दी गई है। नबीन पार्टी-सरकार-संघ के कामकाज के एक नए मॉडल का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

बांग्लादेश चुनाव हमारे लिए भी ख़ास

मिन्हाज

बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने जा रहे चुनाव में तीन ताकतें मैदान में हैं। पहली, मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार, जिसे पाकिस्तान से जुड़े इस्लामिक समूहों का समर्थन है। दूसरी, बीएनपी, जिसकी कमान पिछले ही माह दिवंगत हुई खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के हाथों में है।

तीसरी, वो विदेशी ताकतें, जो बांग्लादेश की अस्थिरता में अपने हित साध रही हैं। इनमें चीन और पाकिस्तान भारत-विरोधी तत्वों का समर्थन करते हैं। फिर अमेरिका है, जो हसीना सरकार की जगह अपने अनुकूल शासन चाहता है। शेख हसीना सरकार ने वर्षों तक अमेरिका को बंगाल की खाड़ी स्थित सेंट मार्टिन द्वीप तक पहुंच बनाने से रोके रखा था। म्यांमार से केवल पांच किलोमीटर दूर इस द्वीप का गहरा भू-रणनीतिक महत्व है। गए साल शेख हसीना के पलायन के बाद से भारत ने यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार के साथ सीधे टकराव के बजाय शांत कूटनीति को प्राथमिकता दी। लेकिन हसीना को शरण देने से इस्लामवादी नियंत्रण वाली यूनुस सरकार भारत से नाराज हो गई। हसीना का 15 वर्ष का शासन भारत-बांग्लादेश संबंधों में सबसे उत्पादक और सौहार्दपूर्ण रहा है। इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा उन्हें जबरन हटाया जाना भारत के लिए बड़ा झटका था। बांग्लादेश को पावर ग्रिड से बिजली सप्लाई के चलते भारत आज भी बांग्लादेश पर दबाव बनाए रखने की हैसियत में है।

चुनाव नजदीक आते ही हसीना मुखर हो गई हैं। ढाका छोड़ने के बाद पिछले सप्ताह अपने पहले सार्वजनिक भाषण में उन्होंने बांग्लादेशियों से यूनुस सरकार और उनके कट्टरपंथी समर्थकों को उखाड़ फेंकने की अपील की। भारत बीएनपी की जीत की उम्मीद कर रहा है। ओपिनियन पोल्स में बीएनपी को 70% से अधिक समर्थन मिल रहा है। बीएनपी अतीत में भारत-विरोधी रही है, लेकिन रहमान के नेतृत्व में पार्टी ने धर्मनिरपेक्ष, बहुलतावादी, आर्थिक विकास पर केंद्रित और भारत से सहयोग रखने वाली सरकार चलाने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। बीएनपी की मुख्य प्रतिद्वंदी जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) है। बीएनपी और जमात के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो चुकी हैं। हसीना की अवामी लीग के खिलाफ पहले दोनों ही दल सहयोगी थे, लेकिन अब लीग को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

जहां बीएनपी कट्टर इस्लामवाद से मध्यमार्गी विचारधारा की ओर आई है, वहीं जमात विषैले कट्टरपंथ की ओर बढ़ी है। जमात के संयोजक नाहिद इस्लाम ने टी-20 विश्व कप में भारत में मैच नहीं खेलने संबंधी सरकारी फैसले में अहम भूमिका निभाई थी। नतीजतन, बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड की टीम को शामिल किया गया। बांग्लादेश में भारत-विरोधी भावना तब चरम पर आ गई, जब आईपीएल से तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को हटा दिया गया। भारत-विरोधी गुस्सा इतना गहरा था कि इससे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भारी वित्तीय नुकसान तक उठाना पड़ा। मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार 'जो टीमें टूर्नामेंट में दूसरे दौर से आगे नहीं बढ़तीं, उन्हें भी 3,82,500 डॉलर की इनामी राशि मिलती है। 9वें से 12वें स्थान पर रहने वाली टीमों को 2,47,500 डॉलर मिलते हैं। 13वें से 20वें स्थान पर रहने वाली टीमों को 2,25,000 डॉलर मिलते हैं। मैच जीतने पर हर टीम को 31,154 डॉलर अतिरिक्त मिलते हैं। हिस्सा लेने वाली टीमों को आईसीसी तीन से पांच लाख डॉलर तक की फीस भी देता है, जो स्थानीय क्रिकेट बोर्ड को जाती है।' आम चुनाव से पहले भारत ने बांग्लादेश के साथ तनाव घटाने की कोशिश की है। लेकिन चुनाव जीत कर प्रधानमंत्री पद संभालने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति भारत को सख्त रवैया अपनाने की जरूरत होगी। यहां दांव पर बहुत कुछ लगा है। हमारे यहां पश्चिम बंगाल और असम में लाखों बांग्लादेशी शरणार्थी रह रहे हैं। इस बीच, पाकिस्तान बांग्लादेश में नया भारत-विरोधी 'पूर्वी पाकिस्तान' बनाने की कोशिश में है। चीन बांग्लादेश में बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं की तैयार कर रहा है। अमेरिका ने भी बांग्लादेश में सक्रियता बढ़ा दी है। क्या रहमान की बीएनपी वास्तव में एक समावेशी और सुधारवादी सरकार बना पाएगी? शेख हसीना इस पर आश्वस्त नहीं हैं। लेकिन भारत उम्मीद करेगा कि निर्वासन में बिताए एक दशक ने बीएनपी के रहमान का रुख नरम किया होगा। जमात जैसे कठोर इस्लामवादी विपक्ष के सामने रहमान को चरमपंथ के बजाय मध्यमार्गी विचारधारा से शासन चलाने पर मजबूर होना पड़ेगा। भारत बीएनपी की जीत की उम्मीद कर रहा है। यह अतीत में भारत-विरोधी पार्टी रही है, लेकिन हाल में इसने धर्मनिरपेक्ष, बहुलतावादी, विकास पर केंद्रित और भारत से सहयोग रखने वाली सरकार चलाने की प्रतिबद्धता जाहिर की है।

साप्ताहिक शहर सत्ता

सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कोई नजर डालने की हिम्मत न करेः शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को रणनीतिक रूप से अहम सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यह भारत की भूमि है और कोई भी इसे धमकी देने या इससे छेड़छाड़ करने की कोशिश न करे. उन्होंने साफ कहा कि देश की सुरक्षा से जुड़े इस इलाके पर किसी भी तरह की नजर या बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

'चिकन नेक' को लेकर सख्त चेतावनी

सिलीगुड़ी कॉरिडोर को आमतौर पर 'चिकन नेक' कहा जाता है. इस मुद्दे पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में कुछ लोगों ने नारे लगाए थे कि वे इस 'चिकन नेक' को काट देंगे. उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि यह भारत की जमीन है और इस पर कोई हाथ नहीं लगा सकता.

बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बयान

अमित शाह सिलीगुड़ी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा, 'अरे भाई, तुम इसे कैसे काटोगे? क्या यह तुम्हारे बाप की जमीन है? यह भारत की जमीन है.' उनके इस बयान पर सभा में मौजूद कार्यकर्ताओं ने जोरदार समर्थन जताया.

दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का जिक्र

केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि इस तरह के नारे लगाने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया था. उन्होंने कहा कि कानून ने अपना काम किया और ऐसे तत्वों को जेल भेजा गया.

'इंडिया' गठबंधन पर लगाए आरोप

अमित शाह ने आरोप लगाया कि विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन के नेताओं ने गिरफ्तार लोगों को छुड़ाने की कोशिश की. उन्होंने दावा किया कि गठबंधन के सांसदों ने उनकी तरफ से पैरवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का रुख किया, लेकिन अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी.

क्या है सिलीगुड़ी गलियारा

'चिकन नेक' के नाम से मशहूर सिलीगुड़ी गलियारा पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में स्थित है. यह करीब 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा और लगभग 60 किलोमीटर लंबा संकरा इलाका है, जो भारत के मुख्य भूभाग को उत्तर-पूर्वी राज्यों से जोड़ता है. सुरक्षा और रणनीतिक दृष्टि से इसे देश का बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

आंध्र में बिगड़ी कानून व्यवस्था, राष्ट्रपति और पीएम मोदी से तत्काल कार्रवाई की गुहार

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश की जनता ने राज्य में बढ़ती अराजकता, कथित सियासी दुश्मनी और अपराधिक गतिविधियों को लेकर देश के सर्वोच्च नेतृत्व का दरवाजा खटखटाया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो रही एक गंभीर अपील के जरिए लोगों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शासक दल की गतिविधियों पर अंकुश लगाने की मांग की है.

लोगों ने क्या अपील की

लोगों का कहना है कि आम नागरिक अब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. यह अपील उस समय सामने आई है जब राज्य में राजनीतिक तनाव और अपराधों को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं. पिछले कुछ दिनों से राज्य के कई हिस्सों से शासक पक्ष की ओर से की जा रही धक्केशाही और हिंसा की शिकायतें सामने आ रही हैं. जनता द्वारा की गई यह अपील किसी राजनीतिक दल से जुड़ी हो या आम नागरिकों का दर्द, इसमें स्थिति की गंभीरता साफ झलक रही है.लोगों का कहना है कि राज्य में कानून का राज समाप्त हो गया है और जरूरतमंदों को न्याय नहीं मिल पा रहा है. अपील में खास तौर पर चेतावनी दी गई है कि यदि तत्काल सुधार नहीं किया गया तो आंध्र प्रदेश की यह बदहाल स्थिति पूरे देश की छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचा सकती है.

सत्ता के दुरुपयोग के कई मामले

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि हाल के दिनों में सत्ता के दुरुपयोग के कई मामले सामने आए हैं, जिससे आम जन में भारी रोष है. लोगों का विश्वास टूट रहा है और वे अब केंद्र सरकार के हस्तक्षेप को ही अंतिम उम्मीद के रूप में देख रहे हैं।

ईरान के चाबहार प्रोजेक्ट को झटका!

क्या ट्रंप के असर की वजह से हुआ ऐसा?

नई दिल्ली। केंद्रीय बजट में इस बार चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई. अमेरिका की ओर से ईरान पर नए प्रतिबंध लगाये जाने की पृष्ठभूमि में यह कदम उठाया गया है. भारत पिछले कुछ सालों से ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में जारी विशाल कनेक्टिविटी परियोजना पर हर साल 100 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है. चाबहार बंदरगाह के विकास में भारत एक प्रमुख साझेदार है.

अमेरिका ने ईरान पर लगाए कड़े प्रतिबंध

अमेरिका ने सितंबर 2025 में ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन चाबहार बंदरगाह परियोजना पर लागू प्रतिबंधों से भारत को छह महीने की छूट दी थी. यह छूट 26 अप्रैल 2026 को खत्म होने जा रही है. विदेश मंत्रालय ने पिछले महीने कहा था कि भारत चाबहार बंदरगाह परियोजना से संबंधित मुद्दे पर अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है. न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर ट्रंप प्रशासन की ओर से 25 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने की धमकी के बाद भारत इस प्रोजेक्ट से संबंधित अलग-अलग विकल्पों पर विचार कर रहा है.

क्या है चाबहार पोर्ट का उद्देश्य?

भारत और ईरान मिलकर चाबहार पोर्ट का विकास कर रहा है ताकि कनेक्टिविटी और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा मिल सके. दोनों देश चाबहार बंदरगाह को इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) का अभिन्न अंग बनाने के लिए भी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं. INSTC भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए 7,200 किलोमीटर लंबी परिवहन परियोजना है.

डूबेगी बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री

नई दिल्ली। भारत के खिलाफ मोहम्मद यूनुस सरकार के तल्ख तेवरों को तगड़ा झटका लगा है. रविवार (1 फरवरी, 2026) को भारत सरकार ने जो बजट पेश किया है, उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए तगड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिससे बांग्लादेश की रीढ़ की हड्डी यानी उसकी टेक्सटाइल इंटस्ट्री बड़ी बुरी तरह प्रभावित होगी. हाल ही में यूरोपीयन यूनियन के साथ हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग के लिए बड़ा झटका है.रविवार (1 फरवरी, 2026) को वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने सिल्क प्रोडक्शन, मशीनरी सपोर्ट, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम और टेक्सटाइल सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट की घोषणा की है.

बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक

बजट में लेबर-इंटेंसिव टेक्सटाइल सेक्टर के लिए मजबूत पॉलिसी पर भी जोर दिया गया है, जिसका मकसद आत्मनिर्भरता, रोजगार, इनोवेशन और ग्लोबल कॉम्पटिटिवनेस को बढ़ावा देना है. बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत के लिए हमेशा से चुनौती रही है. बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट का निर्यातक है, जबकि भारत छठे नंबर है. साल 2024 में बांग्लादेश ने 52.9 अरब डॉलर का कपड़ा निर्यात किया था, जबकि भारत ने टेक्सटाइल्स, अपैरल और हैंडीक्राफ्ट का कुल 37.7 अरब डॉलर का निर्यात किया था. जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, तब से भारत को लेकर उनका रवैया थोड़ा तल्ख रहा है. वहीं, पाकिस्तान के साथ भी बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ने लगी हैं. ऐसे में भारत ने भी द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक रूप से परिभाषित करना शुरू कर दिया है, जिसकी झलक बजट में देखने को मिली है. भारत कपड़ा बाजार को आकर्षक बनाने की तैयारी कर रहा है.

अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की आहट!

नई दिल्ली। खाड़ी देशों में अमेरिका और ईरान युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है. इसकी कई वजह सामने आई हैं. इनमें पहली वजह इजराइल और खाड़ी देशों में एंटी रॉकेट सिस्टम एक्टिव किया गया है. अब एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती से माना जा रहा है कि ईरान पर हमले की तैयारी है. साथ ही जवाबी कार्रवाई करने और उससे निपटने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है. युद्ध संकट के बीच दूसरी जो सबसे बड़ी सुगबुगाहट देखने को मिली है, उनमें यह कि गल्फ कंट्री कुवैत और बहरीन में रविवार को इमरजेंसी पब्लिक वॉर अलार्म सिस्टम टेस्ट किया गया है. इन लोगों को अलार्म बजने के बाद सुरक्षित जगह पर आश्रय लेने का एहतियातन तौर पर निरीक्षण किया गया है. ईरान आर्मी चीफ ने अपने कमांडर्स से कहा है कि अमेरिका या इजराइल उनके सेंट्रल कमांड कंट्रोल सिस्टम और कम्युनिकेशन को नष्ट कर देता है, तो वो किसी भी ऑर्डर का इंतजार नहीं करेंगे. उन्हें जो टास्क दिए गए हैं, उनपर सीधा अटैक करेंगे. इसके अलावा खबर है कि ईरान ने पूरे देस में वॉर सायरन बजाए हैं.

चीन और अमेरिका में छिड़ी नई जंग!

अब चीनी करेंसी के दम पर ट्रंप को आंख दिखाएंगे जिनपिंग

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी डॉलर को इंटरनेशनल इकोनॉमी में बड़ी चुनौती दी है. उन्होंने कहा है कि चीन को अपनी करेंसी युआन को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि दुनिया के देश इसे इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी के रूप में इस्तेमाल करें और जमा करें. फिलहाल वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की हिस्सेदारी 58-60% के आसपास है. शी जिनपिंग ने यह बात कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख थ्योरेटिकल जर्नल 'किउशी' में छपे एक लेख में कही है.

युआन को ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनाने की कोशिश

यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. शी जिनपिंग ने साफतौर पर कहा कि युआन का अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निवेश और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होना चाहिए. इससे युआन को ग्लोबल रिजर्व करेंसी का दर्जा मिलेगा. हालांकि उन्होंने डॉलर का नाम सीधे नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ है कि चीन अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहता है.पिछले साल चीन के कुल 6.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी व्यापार का एक-तिहाई हिस्सा लोकल करेंसी यानी युआन में सेटल हुआ. चीन ने रूस के साथ मिलकर क्रॉस-बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम (CIPS) नाम का पेमेंट सिस्टम बनाया है, जो SWIFT का विकल्प है. रूस से तेल-गैस खरीदते समय युआन का इस्तेमाल बढ़ रहा है. चीन ने लगभग 50 देशों के साथ करेंसी स्वैप समझौते किए हैं. BRICS देशों में कॉमन करेंसी और BRICS Pay सिस्टम की बात चल रही है.

चीन का कैपिटल मार्केट मजबूत नहीं

चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा कि चीन की बैंकिंग एसेट्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और कैपिटल मार्केट बहुत बड़े हैं, लेकिन अभी 'बड़ा है पर मजबूत नहीं'. एक मजबूत फाइनेंशियल पावरहाउस बनने में समय लगेगा. इसके लिए मजबूत करेंसी, सेंट्रल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अंतरराष्ट्रीय केंद्र, अच्छी निगरानी और टैलेंट की जरूरत है. चीन का अपना वित्तीय विकास मॉडल पश्चिमी मॉडल से अलग होगा और मजबूत आर्थिक नींव पर टिका होगा. पिछले एक साल में युआन डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों के बावजूद चीन ने 2025 में रिकॉर्ड ट्रेड सरप्लस बनाया और अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखा।

ईशान किशन या संजू सैमसन? वर्ल्ड कप में कौन करेगा ओपनिंग

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया के लिए ओपनिंग कौन करेगा? इस क्रम के लिए संजू सैमसन और ईशान किशन के बीच जंग छिड़ी है. एक तरफ सैमसन हैं, जिन्हें टीम मैनेजमेंट का सपोर्ट करता आया है लेकिन दूसरी ओर ईशान किशन रनों का अंबार लगा रहे हैं. सुनील गावस्कर कह चुके हैं कि वो अपनी प्लेइंग इलेवन में सैमसन को जगह नहीं देंगे. दरअसल कप्तान सूर्यकुमार यादव ने खुद इस सवाल का जवाब देकर सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है.

ईशान या संजू, किसे मिलेगी ओपनिंग?

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जियोहॉटस्टार से बातचीत में बताया कि संजू सैमसन और ईशान किशन में से ओपनिंग किसे मिलेगी, इसका फैसला 7 फरवरी को लिया जाएगा. इसी दिन टीम इंडिया अपने टी20 वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत करेगी, जहां उसे यूएसए से भिड़ना है. सूर्यकुमार यादव ने साफ कहा कि 7 फरवरी को जब प्लेइंग इलेवन घोषित होगी, तभी पता चल पाएगा कि टीम इंडिया में ओपनिंग की जिम्मेदारी किसे मिलेगी.

किसके आंकड़े बेहतर?

ईशान किशन की बात करें तो उन्होंने करीब दो साल बाद टीम इंडिया में वापसी की है. न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में उन्होंने 4 पारियों में बैटिंग की और 53.75 के शानदार औसत से 215 रन बनाए. इस सीरीज में उनके बल्ले से एक शतक और एक अर्धशतक भी आया. तिरुवनंतपुरम में खेले गए अंतिम टी20 मैच में उन्होंने 43 गेंदों में 103 रनों की शतकीय पारी खेली थी. दूसरी ओर संजू सैमसन ने साल 2024 में पांच पारियों के भीतर 3 शतक लगा दिए थे. मगर उसके बाद बतौर ओपनर उनका प्रदर्शन बहुत खराब रहा है. जनवरी 2025 से लेकर अब तक सैमसन ने बतौर ओपनर 11 पारियों में बैटिंग की है, जिनमें उनके बल्ले से एक भी फिफ्टी नहीं निकली है. इन 11 पारियों में वो केवल 134 रन बना पाए हैं।

सूर्यकुमार यादव ने कोहली का रिकॉर्ड किया ध्वस्त

नई दिल्ली। भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच खेली गई पांच मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला पूरी तरह से सूर्यकुमार यादव के नाम रहा. तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारतीय कप्तान ने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि रिकॉर्ड बुक में उनका नाम दर्ज हो गया. इस मुकाबले के साथ ही सूर्या ने विराट कोहली का एक बड़ा रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया. न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरज ने सूर्या ने 242 रन बना डाले. इसी के साथ ही सूर्या एक टी20 इंटरनेशनल सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक सीरीज में 231 रन बनाए थे. सूर्या ने इस आंकड़े को पार कर नया कीर्तिमान रच दिया है. पांचवें टी20 मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने आक्रामक शुरुआत की. ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर तक बल्लेबाजों ने खुलकर शॉट्स खेले. 20 ओवर के खेल में भारत ने 5 विकेट खोकर 271 रन बना डाले, जो न्यूज़ीलैंड के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं था. इस बड़े स्कोर में सूर्यकुमार यादव की पारी बेहद अहम रही.सूर्यकुमार यादव ने इस मैच में 4 चौके और 6 छक्के जड़ते हुए 30 गेंदों पर 63 रन बना डाले.

सीरीज में शानदार वापसी

इस सीरीज से पहले सूर्यकुमार यादव की फॉर्म को लगातार आलोचना हो रही थी. उनके ऊपर कप्तानी के साथ बल्लेबाजी का दबाव साफ नजर आ रहा था. हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज में उन्होंने पूरी तरह से खुद को साबित किया. पांच मैचों में सूर्या ने तीन अर्धशतक लगाए और कुल 242 रन बनाए. यह प्रदर्शन बताता है कि बड़े मैचों के खिलाड़ी क्यों कहे जाते हैं।

2026 टी20 वर्ल्ड कप में भारत से नहीं खेलेगा पाकिस्तान

नई दिल्ली। 2026 टी20 वर्ल्ड कप को लेकर PCB ने अजीब फैसला लिया है. इस वैश्विक टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम भारत से मैच नहीं खेलेगी. यह महामुकाबला 15 फरवरी को होना था. पाकिस्तान सरकार का कहना है कि टीम 15 फरवरी 2026 को भारत के खिलाफ होने वाले मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी. रविवार को पाकिस्तान सरकार ने एलान किया कि उनकी टीम 7 फरवरी से शुरू हो रहे 2026 टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी, लेकिन 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी. पाकिस्तान ने यह फैसला बांग्लादेश के टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद लिया है।

भारत और EU के बीच FTA पर बिलबिलाया पाक

भारत और यूरोपीय यूनियन (EU) के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) ने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है. पाकिस्तान को डर है कि कहीं भारत के साथ साइन हुए FTA के चलते कहीं EU में उसका एक्सपोर्ट कम न हो जाए. वैसे भी पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स और एनालिस्ट्स ने पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि यह डील पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े एक्सपोर्ट मार्केट में उसकी स्थिति कमजोर बना सकती है क्योंकि यूरोपीय बाजारों में भारतीय उत्पादों को बड़े पैमाने पर टैरिफ-फ्री एक्सेस मिलेगा. इससे वहां भारतीय प्रोडक्ट्स की कीमतें कम होंगी, मांग बढ़ेगी और पाकिस्तान के मुनाफे पर आंच आएगी. फिलहाल पाकिस्तान भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच नए साइन हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के असर की समीक्षा में जुटा हुआ है. PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, वीकली प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा कि इस्लामाबाद इस एग्रीमेंट से वाकिफ है और EU के साथ अपने व्यापारिक संबंधों के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा, "पाकिस्तान और EU के बीच संबंध लंबे समय से दोस्ताना और आपसी फायदे वाला रहा है. पाकिस्तान के लिए EU की जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस (GSP+) एक विन-विन मॉडल साबित हुई है।

मल्टीबैगर स्टॉक ने 1 लाख के 1 साल में बना दिए 4.7 लाख

नई दिल्ली। पिछले साल बजट पेश होने के बाद से अमेरिकी टैरिफ, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव जैसे तमाम जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताओं के चलते शेयर बाजार

दबाव में रहा. हालांकि, बाजार में तमाम उतार-चढ़ाव के बीच भी एक स्टॉक ने अपने निवेशकों का जमकर मुनाफा कराया है. आज हम आपको एक ऐसे ही शेयर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने अपने शेयरहोल्डर्स को उनके निवेश पर जबरदस्त रिटर्न दिया है.

बंपर रिटर्न देकर मल्टीबैगर बना शेयर

यहां सिंथिको फाइल्स (Synthiko Foils) की बात की जा रही है, जिसके शेयर में पिछले एक साल में 363 परसेंट का उछाल आया है. अप्रैल 2025 से इसके शेयर एक तरफा अच्छा प्रदर्शन करते जा रहे हैं. इस दौरान शेयरों की कीमत 455.60 रुपये से बढ़कर 1,855 प्रति शेयर पर पहुंच गया है. इस बीच यह 2,610 का नया रिकॉर्ड हाई भी बना चुका है. अप्रैल 2025 में स्टॉक में 54 परसेंट और सितंबर 2025 में 71 परसेंट की तेजी आई. पिछले एक साल में शेयर की कीमत में भारी बढ़ोतरी से निवेशकों की दौलत में काफी इजाफा हुआ है. एक साल पहले स्टॉक में किया गया1 लाख का निवेश आज बढ़कर 4.7 लाख रुपये तक पहुंच गया है. खास बात यह है कि इसका फायदा ज्यादातर रिटेल निवेशकों को हुआ है, दिसंबर तिमाही के आखिर में कंपनी में सामूहिक रूप से 34.2 परसेंट की हिस्सेदारी थी. 2 लाख से ज्यादा पूंजी वाले रिटेल निवेशकों के पास कंपनी में 13.16 परसेंट की मालिकाना हिस्सेदारी है, जो सिंथिको फॉइल्स की ग्रोथ स्टोरी में व्यक्तिगत शेयरधारकों की मजबूत भागीदारी को दिखाता है. 1994 में बनी यह कंपनी एल्युमिनियम पैकेजिंग फॉइल बनाने, उसकी सप्लाई और एक्सपोर्ट करने का काम करती है, जिसमें एल्युमिनियम फॉइल, लिडिंग फॉइल, टू-प्लाई बनाती है।

कहानी उन दिनों की

वित्त मंत्री पर जब-जब आया संकट तो PM ने पेश किया बजट

देश का आम बजट 1 फरवरी को पेश होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार संसद में बजट पेश करेंगी. यह अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है. आमतौर पर बजट पेश करने की जिम्मेदारी वित्त मंत्री की ही होती है, लेकिन देश में कई ऐसे मौके भी आए जब देश के प्रधानमंत्रियों को आगे आकर बजट पेश करना पड़ा. आइए जानते हैं कि ऐसा कब और क्यों हुआ?

जवाहर लाल नेहरू

सबसे पहले यूनियन बजट पेश करने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे. उन्होंने वित्तीय वर्ष 1958-59 के लिए बजट पेश किया था. दरअसल, उस समय के वित्त मंत्री टीटी कृष्णामाचारी का नाम मुद्रा घोटाले में आने के चलते उन्हें 12 फरवरी, 1958 को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था. जस्टिस छागला कमीशन ने मुंद्रा घोटाले में उन्हें भ्रष्टाचार का दोषी पाया था. उनके जाने के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने आगे आकर वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला और खुद बजट पेश किया.अपना बजट भाषण शुरू करते हुए उन सभी असामान्य परिस्थितियों का जिक्र किया, जिसके तहत वह बजट पेश कर रहे थे. उनके पेश किए गए इस बजट में 'गिफ्ट टैक्स' प्रस्ताव रखा गया. इसमें 10 हजार रुपये से ज्यादा की संपत्ति के ट्रांसफर को 'गिफ्ट टैक्स' के दायरे में लाया गया. हालांकि, पत्नी को 1 लाख रुपये तक का गिफ्ट देने पर टैक्स नहीं लगने का भी जिक्र किया गया.

इंदिरा गांधी

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी 1970 में यूनियन बजट पेश किया था. 1969 में जब मोरारजी देसाई ने वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था, तो इंदिरा गांधी को आगे आना पड़ा. वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालते हुए उन्होंने फरवरी 1970 में बजट पेश किया. दरअसल, पंडित जवाहर लाल नेहरू के निधन के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनीं, जिसका मोरारजी देसाई ने विरोध किया था. पार्टी में अंदरूनी कलह और इंदिरा गांधी से मतभेद के चलते कांग्रेस ने उन्हें 12 नवंबर, 1969 को पार्टी से बाहर निकाल दिया. इसके बाद इंदिरा गांधी ने वित्त मंत्रालय का प्रभार संभालते हुए 28 फरवरी, 1970 को बजट पेश किया, जिसमें 'गिफ्ट टैक्स' के लिए लिमिट को 10000 से घटाकर 5000 कर दिया गया. इस दौरान इनडायरेक्ट टैक्स में भी बड़ा बदलाव करते हुए सिगरेट पर टैक्स को 3 परसेंट से बढ़ाकर सीधे 22 परसेंट कर दिया गया.

राजीव गांधी

वित्त वर्ष 1987-88 का बजट तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पेश किया था, जिसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ-साथ आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया. अपने पेश किए इस बजट में उन्होंने पहली बार कॉर्पोरेट टैक्स का प्रस्ताव पेश किया था. इसके तहत, घरेलू और विदेशी कंपनियों की कमाई पर टैक्स लगाया गया. बोफोर्स तोपों की डील को लेकर हुए घोटाले की जांच के मद्देनजर वीपी सिंह का राजीव गांधी से विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा था. इसके चलते एक तरह से दबाव में आकर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा।

साप्ताहिक शहर सत्ता

प्रदेशभर में कांग्रेस का धरना मुख्य मार्गों में चक्काजाम

धान खरीदी की मियाद बढ़ाने व मनरेगा में बदलाव के खिलाफ आंदोलन

रायपुर। प्रदेश में धान खरीदी की मियाद बढ़ाने और मनरेगा कानून में बदलाव के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतरी। वहीं मोदी सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रामक विरोध प्रदर्शन किया। शहरी क्षेत्रों में इन दोनों मुद्दों को लेकर सरकार पर हमले किए गए। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में धान खरीदी के मुद्दे पर फोकस करते हुए घेराबंदी की गई। सभी ब्लॉक और जिला मुख्यालयों में कांग्रेसी धरने पर बैठे। धरने के बाद संबंधित क्षेत्रों के प्रमुख मार्गों में अचानक चक्का जाम कर दिया। सड़कों को घेरकर बैठते ही वहां अफरातफरी मची। करीब घंटे भर आवाजाही भी बाधित रही। प्रतीकात्मक चक्काजाम और नारेबाजी के बाद कांग्रेसी वहां से हटे।

राजधानी में भी कांग्रेस ने ताकत दिखाई। शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने रायपुर की चारों विधानसभा क्षेत्रों में धरना दिया। महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर पुष्पांजलि के बाद चारों विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेसी धरने पर बैठे। रायपुर दक्षिण विधानसभा के राजीव गांधी चौक में धरने में सभी वरिष्ठ नेताओं को जुटाकर सरकार पर हमले किए। यहां बड़ी तादाद में अपने समर्थकों के साथ पहुंचे पूर्व महापौर एजाज ढेबर ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करते हुए माहौल बनाया।

हालांकि शहर अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन की अगुवाई में दक्षिण के राजीव गांधी चौक के अलावा रायपुर ग्रामीण के बोरियाखुर्द, रायपुर पश्चिम के पहाड़ी चौक, रायपुर उत्तर के फाफाडीह चौक में कांग्रेसी धरने पर बैठे। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर मनरेगा में बदलाव का विरोध कर कानून बहाल करने की मांग की। शहर अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन ने आरोप लगाए कि सरकार ने योजना का मूल स्वरूप बदलकर श्रमिकों के साथ धोखा किया है। कांग्रेस अपना संघर्ष जारी रखते हुए जनजागरण अभियान चलाएगी। प्रदर्शन में वरिष्ठ नेता प्रमोद चौबे, प्रमोद दुबे, एजाज ढेबर, पंकज शर्मा, संजय पाठक, गिरीश दुबे, घनश्याम राजू तिवारी, कन्हैया अग्रवाल, महेन्द्र छाबड़ा, दीपक मिश्रा, शिवसिंह ठाकुर, जागेश्वर राजपूत समेत बड़ी तादाद में कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी रही।

प्रदेश के एग्रोक्लाइमेट के अनुरूप एक हफ्ते में बनेगी विशेष नीति

रायपुर। केंद्र सरकार के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिकों और राज्य अफसरों की टीम आगामी एक सप्ताह में छत्तीसगढ़ के एग्रोक्लाइमेट के अनुरूप विशेष नीति बनाएगी। केन्द्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभागीय समीक्षा के दौरान इस पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने फसल विविधिकरण को बढ़ावा देना है। साथ ही छोटी जोत के किसानों को पशुपालन, मत्स्यपालन, वानिकी जैसी सहायक गतिविधियों में भी बढ़ावा देना है। मंत्रालय में केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान दिशा-निर्देश भी दिए।

समीक्षा के दौरान केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश में रिसर्च, वैरायटी की समस्या को दूर कर फसलों के विविधिकरण पर काम किया जाएगा। यहां अच्छा काम हो रहा है, लेकिन और बेहतर करने की जरूरत है। अलग-अलग प्रयोग कर कृषि को सशक्त बनाएंगे। अनुसंधान ऐसा होना चाहिए, जिससे सीधे किसानों को लाभमिले। उन्होंने फॉर्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन को मजबूत करने, कृषि यंत्रों के वितरण के फिजिकल वेरिफिकेशन और प्रधानमंत्री धन धान्य जिला योजना की समीक्षा की।

आलाकमान की छग के दिग्गजों को दो टूक एकजुटता से भाजपा के खिलाफ लड़ें

रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पहले निचले स्तर पर संगठनात्मक काडर को मजबूत करे, सक्रिय नेताओं को आगे बढ़ाए और आने वाली लड़ाई के लिए तैयार करें। प्रदेश के सभी नेता अथ भाजपा सरकार के खिलाफ एकजुट होकर हुंकार भरें। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरणे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गजों की बैठक में कुछ इसी तरह की नसीहतें दी गई। प्रभारी महासचिव सचिन पायलट द्वारा छत्तीसगढ़ में संगठन के कामकाज की रिपोर्ट पेश करने के बाद आगामी छह माह की कार्ययोजना को लेकर भी रणनीति तय कर दी गई है। संगठनात्मक गतिविधियों के आलावा एसआईआर और मनरेगा आंदोलन को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन की अब तक की गतिविधियों को लेकर पेश की गई रिपोर्ट पर राष्ट्रीय नेताओं ने इतना जरूर कहा कि भाजपा सरकार की नाकामियों के खिलाफ लड़ाई और तेज होनी चाहिए। एआईसीसी के टास्क को पूरा करने के मामले में जरूर संतुष्टि जताई गई लेकिन राज्य में भाजपा सरकार के खिलाफ ज्वलंत मुद्दों पर अब आक्रामकता के साथ भिड़ने के भी दो टूक निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक राज्य के वरिष्ठ नेताओं से स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि वे अब अलग-अलग राह चलने के बजाय एकजुटता के साथ मुद्दों पर हमले करें। इससे पहले संगठन का कॉडर निचले स्तर से मजबूत बनाना होगा। सभी स्तर की

कमेटियों की कार्यकारिणी आगामी माह तक घोषित कर सबको टॉस्क सीप दिया जाए। करणे व राहुल ने प्रभारी सचिन पायलट से स्पष्ट कह दिया कि निक्रिय लोगों को हटाकर सक्रिय कार्यकर्ताओं को ही महत्व देकर जिम्मेदारी सौंपें। प्रभारी समेत प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से यह भी पूछा गया कि वे भविष्य में भाजपा सरकार की नाकामियों की सामने लाकर किस रणनीति के तहत काम करेंगे। बैठक में आगामी छह माह की रणनीतियों की भी अंतिम रूप दे दिया गया। राष्ट्रीय नेताओं ने छत्तीसगढ़ में एसआईआर की पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ी और लाखों मतदाताओं का नाम काटे जाने को गंभीर माना। वहीं इस मामले भाजया की सांठगांठ उजागर कर आम लोगों की सच्चाई बताने पर भी सहमति बनी।

नारायणपुर में 'अबूझमाड़ पीस हॉफ मैराथन-2026' को हरी झंडी दिखाई

अबूझमाड़ अब अमन और शांति का संदेश दे रहा : साय

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार को नारायणपुर में 'अबूझमाड़ पीस हॉफ मैराथन-2026' को हरी झंडी दिखाई और कहा कि अबूझमाड़ को कभी माओवादियों का मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन आज यह अपनी धरती से देश-दुनिया को अमन और शांति का मजबूत संदेश दे रहा है। अबूझमाड़ की धरती से शांति, सद्भाव और विकास का सशक्त संदेश देते हुए 'अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन-2026' का भव्य और ऐतिहासिक आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने सुबह नारायणपुर के हाईस्कूल परिसर के समीप आयोजित हाफ मैराथन के धावकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा सांकेतिक रूप से स्वयं भी दौड़ लगाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विजयी प्रतिभागियों को प्रदान किए जाने वाले मेडल का अनावरण भी किया। इस दौरान साय ने कहा 'अबूझमाड़ की धरती से पूरे देश और दुनिया को अमन और शांति का मजबूत संदेश दिया जा रहा है। यह वही अबूझमाड़ है, जहां कभी आम नागरिकों और जवानों का पहुंचना भी कठिन था, लेकिन आज सकारात्मक वातावरण के कारण हजारों लोग यहां एकत्रित हुए हैं। माओवाद से मुक्त बस्तर की दिशा में युवा वर्ग का जोश और उत्साह यह संकेत दे रहा है कि जल्द ही यह क्षेत्र खुशियों से आबाद होगा।'

10 हजार धावकों ने हिस्सा लिया

21 किलोमीटर लंबी 'हाफ मैराथन' नारायणपुर से बासिंग तक आयोजित की गई, जिसमें 60 से अधिक विदेशी प्रतिभागियों सहित बस्तर संभाग, प्रदेश और अन्य राज्यों के 10 हजार से अधिक धावकों ने भाग लिया।

अर्पित सूर्यवंशी रायपुर शहर जिलाध्यक्ष नियुक्त

रायपुर। भारतीय जनता युवा मोर्चा के शेष 13 जिलाध्यक्षों की शुक्रवार को घोषणा कर दी गई। जिलाध्यक्ष के साथ-साथ महामंत्री भी नियुक्त किए गए। रायपुर शहर जिलाध्यक्ष की कमान अर्पित सूर्यवंशी और शंकर साहू को जिला महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा बस्तर जिलाध्यक्ष अभिलाष यादव, महामंत्री सत्यम झा और रामप्रसाद मौर्य, नारायणपुर जिलाध्यक्ष परमानंद नाग, महामंत्री दिपेंद्र भोयर, बस्तू दत्ता, राजनांदगांव जिलाध्यक्ष चिंटू सोनकर, महामंत्री नोमेश वर्मा व आशुतोष सिंह राजपूत, बेमेतरा जिलाध्यक्ष विजय वर्मा, महामंत्री आयुष शर्मा व गौरव यदु, कवर्धा जिलाध्यक्ष उमंग पाण्डेय, महामंत्री अमित चंद्रवंशी व धानेश्वर जायसवाल, जशपुर जिलाध्यक्ष विजय आदित्य सिंह, महामंत्री गोपाल कश्यप व राजा सोनी, मुंगेली जिलाध्यक्ष राकेश साहू, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिलाध्यक्ष आयश सिंह बोनी, महामंत्री विक्रांत चंद्राकर, कोरबा जिलाध्यक्ष वैभव शर्मा व महामंत्री मोंटी पटेल, धमतरी जिलाध्यक्ष शुभांक मिश्रा, महासमुंद जिलाध्यक्ष अमन वर्मा व महामंत्री प्रखर अग्रवाल के अलावा गौरेला-पेंड्रा मरवाही जिलाध्यक्ष सिद्धार्थ दुबे और महामंत्री अमर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। शेष 13 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था।

राजिम कुंभ कल्प मेला का भव्य शुभारंभ

राजिम छत्तीसगढ़ की आस्था का प्रतीक - राज्यपाल डेका

शहर सत्ता/रायपुर। त्रिवेणी संगम राजिम के पावन तट पर राजिम में आयोजित राजिम कुंभ कल्प मेला के शुभारंभ अवसर पर राज्यपाल श्री रमेन डेका मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राज्यपाल श्री डेका, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल सहित अतिथियों एवं संत-महात्माओं ने भगवान श्री राजीवलोचन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया तथा प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि राजिम की यह पावन भूमि, जहां महानदी, पैरी और सोंढूर नदियों का संगम होता है, अत्यंत पुण्य और ऐतिहासिक महत्व रखती है। उन्होंने कहा कि इस पवित्र स्थल पर आयोजित मेला, जिसे श्रद्धालु 'कल्प कुंभ' के नाम से जानते हैं, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक एवं धार्मिक धरोहर का प्रतीक है।

राज्यपाल ने कहा कि राजिम कुंभ कल्प के अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता और गौरव का अनुभव हो रहा है। मुझे छत्तीसगढ़ की पवित्र नगरी राजिम के कुंभ मेला में आकर अत्यंत शांति महसूस होती है। धर्म, आस्था और संस्कृति के इस संगम राजिम कुंभ मेले में देश के विभिन्न प्रांतों से आए साधु-संतों, श्रद्धालुजनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं कुलेश्वर महादेव तथा राजीव लोचन भगवान, राजिम भक्ति माता से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश और प्रदेश पर अपना आशीर्वाद बनाये रखें जिससे यहां हमेशा सुख-शांति और खुशहाली कायम रहे। राज्यपाल ने आगे कहा कि राजिम माघी पुन्नी मेला छत्तीसगढ़ की आस्था का प्रतीक है। यह एक ऐसा पावन आयोजन है जिसमें छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ-साथ देश भर के विभिन्न भागों से भी श्रद्धालुओं का आगमन होता है। राजिम प्राचीन समय से ही शैव और वैष्णव धर्म के केंद्र के रूप में विख्यात एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहां राजीवलोचन मंदिर में भगवान विष्णु चतुर्भुज स्वरूप में विराजमान है। यहां भगवान शिव कुलेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं।

राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि कुलेश्वरनाथ महादेव, पटेश्वर नाथमहादेव, चंपेश्वर नाथ महादेव, ब्रम्ह्केश्वर नाथ, फनीकेश्वर नाथ महादेव, करपूरेश्वर महादेव की पंचकोशी यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। प्राचीन मंदिरों की बहुलता राजिम को पुरातात्विक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता प्रदान करती हैं। इन मंदिरों में मूर्ति कला के गौरवशाली इतिहास के दर्शन होते हैं।

उन्होंने कहा कि शास्त्रों में माघ के माह पुण्य माह माना गया है। माघ माह के इस पावन अवधि में सदियों से ही पवित्र नदियों एवं त्रिवेणी संगमों में पुण्य स्नान की परंपरा रही है। इस माह छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों में मेले का आयोजन की प्राचीन परंपरा रही है। मेलों का विशेष सामाजिक और सामुदायिक महत्व है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किया तीन दिवसीय सिरपुर महोत्सव का शुभारंभ

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि सिरपुर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके अंतर्गत आधुनिक सड़क, प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग, पर्यटक सुविधा केंद्र एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टूरिस्ट कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल सिरपुर में आयोजित तीन दिवसीय सिरपुर महोत्सव का भव्य शुभारंभ अवसर पर आज मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय उक्त बात कही हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता खाद्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री दयाल दास बघेल ने किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि सिरपुर की ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस गौरवशाली विरासत से परिचित हो सकें। उन्होंने जिलेवासियों को माघी पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महानदी के तट पर स्थित श्री गंधेश्वर महादेव के आशीर्वाद से यह क्षेत्र निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि सिरपुर छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश की सांस्कृतिक पहचान है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि आज जिले को लगभग 200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी गई है, जिससे सड़क, पुल, पेयजल , पर्यटन, पेयजल एवं अधोसंरचना के क्षेत्र में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज यहां मलेशिया,कोरिया, जापान के बौद्ध विचारक पधारे है, उनका मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि सिरपुर में सनातन, बौद्ध और जैन संस्कृति का विस्तार हुआ, यह संस्कृति का अदभुत संगम है। सिरपुर में पर्यटन के विकास की संभावनाओं को देखते हुए सरकार इसे विश्व धरोहरों में शामिल करने गंभीरता से प्रयास कर रही है। देश दुनिया में सिरपुर का नाम होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंचल के विकास के लिए सिरपुर बैराज की स्वीकृति भी जल्दी होगी। सिकासेर जलाशय से कोडार जलाशय में पानी लाने के लिए योजना पर शीघ्रता से कार्य जारी है। इससे क्षेत्र के किसानों को लगातार सिंचाई के लिए पानी मिलेगा।

खाद्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री दयाल दास बघेल ने कहा कि सिरपुर महोत्सव आज जिले की विशिष्ट पहचान बन चुका है। उन्होंने कहा कि सिरपुर महोत्सव के माध्यम से जिले को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है और रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। इससे युवाओं को आगे बढ़ने का मंच मिल रहा है और स्थानीय प्रतिभाओं को नई दिशा प्राप्त हो रही है। प्रभारी मंत्री श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं एवं गरीब वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

संस्कृति बनी पहचान, पुरातत्त्व बना गौरव

- **सचिव डॉ. रोहित यादव ने गिनाई उपलब्धियां**

पर्यटन बना छत्तीसगढ़ का आर्थिक इंजन, दो वर्षों की उपलब्धियों ने बदली तस्वीर

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव और छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक एवं संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्त्व श्री विवेक आचार्य ने नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछले दो वर्षों की उपलब्धियों तथा आगामी कार्ययोजनाओं का विस्तृत विवरण दिया। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर आर्थिक विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और विरासत संवर्धन तीनों क्षेत्रों में समन्वित प्रगति का मॉडल स्थापित किया है।

पर्यटन को मिला उद्योग का दर्जा

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने से निजी निवेश के नए द्वार खुले। राज्य और देश के प्रमुख शहरों में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रमों के माध्यम से 500 करोड़ रुपये से अधिक निजी निवेश सुनिश्चित किया गया। इससे पर्यटन अधोसंरचना, होटल, रिसॉर्ट और साहसिक पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। रामलला दर्शन योजना के तहत आईआरसीटीसी के साथ हुए समझौते के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में लगभग 42 हजार 500 श्रद्धालुओं को विशेष ट्रेनों से अयोध्या दर्शन कराया गया। यह योजना धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। राज्य में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई होम-स्टे नीति लागू की गई। 500 नए होम-स्टे विकसित करने का लक्ष्य है। राज्य सरकार ने 24 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ होम-स्टे नीति 2025-30 को अधिसूचित किया है। यह नीति राज्य भर में नए होम-स्टे के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी और ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है, जो ग्रामीण और समुदाय आधारित पर्यटन का समर्थन करती है, इसके लिए राज्य सरकार ने बजट भी स्वीकृत किया है।

फिल्म सिटी और कन्वेंशन सेंटर- 350 करोड़ की परियोजना

डॉ. रोहित यादव ने बताया कि भारत सरकार की राज्यों को पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता योजना (SASCI) के तहत एकीकृत फिल्म सिटी और कन्वेंशन सेंटर के विकास की मंजूरी मिली है, जिसकी कुल अनुमानित लागत 350 करोड़ रूपए है। भूमि पूजन 24 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के करकमलों से हुई है। यह छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय फिल्म निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम है। चित्रोत्पला फिल्म सिटी के निर्माण से फिल्म निर्माण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को देश और दुनिया में एक नई पहचान मिलेगी। इस महत्वाकांक्षी पहल के माध्यम से छत्तीसगढ़ न केवल फिल्म निर्माण और सांस्कृतिक आयोजनों का एक प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर होगा, बल्कि यह परियोजना राज्य की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को भी नई गति प्रदान करेगी। चित्रोत्पला फिल्म सिटी और ट्राइबल एंड कल्चरल कन्वेंशन सेंटर के निर्माण से स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलेगा, निवेश के नए अवसर सृजित होंगे और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान वैश्विक स्तर पर और अधिक सशक्त होगी।

संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग की उपलब्धियां

संस्कृति एवं पुरातत्त्व के संचालक श्री विवके आचार्य ने बताया कि संस्कृति विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के कलाकारों, साहित्यकारों का चिन्हारी पोर्टल में पंजीयन किया जा रहा है, जिससे विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके। उन्होंने बताया कि चिन्हारी पोर्टल में पंजीकृत 141 कलाकारों एवं साहित्यकारों को वित्तीय वर्ष-2024-25 में लगभग 34 लाख रूपए एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 130 कलाकारों को लगभग 31 लाख रूपए की राशि पेंशन के रूप में प्रदान की गई। इसी तरह कलाकार कल्याण कोष योजना के अंर्तगत कलाकारों और साहित्यकारों अथवा उनके परिवार के सदस्यों की बीमारी, दुर्घटना एवं मृत्यु की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 08 अर्थाभाव ग्रस्त साहित्यकारों/कलाकारों को 2 लाख रूपए एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 44 प्रकरणों हेतु 14 लाख रूपए स्वीकृत किया गया है। राज्य शासन छत्तीसगढ़ के कलाकारों एवं साहित्यकारों के प्रत्येक सुख-दुख में साथी है, तथा संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ राज्य के कलाकारों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है।

बस्तर पंडुम

छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग द्वारा बस्तर पंडुम 2026 का आयोजन बस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति को संरक्षित और प्रचारित करने के लिए किया जा रहा है। यह उत्सव तीन चरणों में 10 जनवरी से 9 फरवरी 2026 तक चलेगा। जनजातीय नृत्य, लोकगीत, नाट्य, वाद्य यंत्र, वेश-भूषा-आभूषण, पूजा पद्धति, हस्तशिल्प, चित्रकला, जनजातीय पेय, पारंपरिक व्यंजन, क्षेत्रीय साहित्य, वन-आधारित औषधीय ज्ञान, पर्यटन और सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ेगी।

पुलिस कमिश्नर ने किया आईटीएमएस का निरीक्षण

आईटीएमएस के कैमरों से ही बनाए जाएंगे शत प्रतिशत ई-चालान

रायपुर। पुलिस कमिश्नर रायपुर डॉ. संजीव शुक्ला ने जयस्तंभ चौक में स्थापित आईटीएमएस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। ई-चालान बनने की प्रक्रिया एवं आईटीएमएस के अंतर्गत स्थापित सिस्टम को समझा। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने आईटीएमएस सिस्टम को समझकर यातायात के अधिकारियों को निर्देश दिया कि कमिश्नरेट प्रणाली के अंतर्गत क्षेत्र में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का कैमरों के माध्यम से ही शत प्रतिशत ई-चालान तैयार करवायें। ई-चालान तैयार कर मोबाईल में टेक्स्ट संदेश एवं व्हाट्सअप संदेश के माध्यम से यातायात नियम तोड़ने वालों को सूचना भेजें। जो लोग ई-चालान की जुर्माना राशि का निर्धारित समयावधि 90 दिन में भुगतान नही करते है उनको नोटिस भेजकर उनका प्रकरण न्यायालय भेजे।

परिवहन विभाग से समन्वय बनाकर ई-चालान बने वाहन एवं वाहन स्वामी का लायसेंस नवीनीकरण, परमिट, फिटनेस, नामांतरण एवं अन्य सेवाओं के साथ साथ बीमा व प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र के अद्यतन सिस्टम को भी रोका जाए। ई-चालान की राशि का भुगतान उपरांत ही सेवाएं प्रारंभ की जाए। पुलिस कमिश्नर से कहा कि इससे ई-चालान की जुर्माना राशि के भुगतान प्रतिशत में वृद्धि होगी साथ ही वाहन स्वामी ई-चालान के अहमियत को समझेगा। शहर में यातायात का अनुशासन स्थापित होगा।

यातायात के अधिकारी जो मौके पर चालान काटते है उसे चालान करना एकदम आवश्यक न हो तो बंद करवाये। ई-चालान डिवाइस सभी को प्रदाय किया गया है उसका उपयोग कर ई-चालान बनायें। उल्लंघन करने वाले वाहनों का फोटों खींचकर ई-चालान बनाने आईटीएमएस सिस्टम में भेजें। ई-चालान बनाने से कार्यवाही में पारदर्शिता रहेगी व लोगों के आरोप-प्रत्यारोप तथा विवादों से मुक्त रहेंगे। गंभीर प्रवृत्ति के उल्लंघन नशा कर वाहन चलाने वाले के विरूद्ध मौके पर एल्कोमीटर से जांच कर तथा नो एंट्री का चालान तैयार कर न्यायालय भेजें।

एल एंड टी कंपनी के मैनेजर श्री दीपक मालवीय को कहा कि बंद सिगनल एवं कैमरों को तत्काल दुरूस्त करायें। यह सिस्टम जनता की सुविधा के लिए स्थापित किया गया है। यातायात पुलिस से सूचना प्राप्त होने पर खराब सिगनल या कैमरों का तत्काल सुधार कार्यवाही होनी चाहिए।

आईटीएमएस सिस्टम के निरीक्षण के दौरान आईटीएमएस के कमांड एंड कंट्रोल रूप में श्री गुरजीत सिंह, श्री सतीश ठाकुर, सहायक पुलिस आयुक्त यातायात एवं श्री दीपक मालवीय मैनेजर, एल एंड टी. कंपनी, यातायात थाना मुख्यालय प्रभारी सउनि. टीकेलाल भोई सहित आईटीएमएस में काम करने वाले यातायात स्टाफ मौजुद थे।

अपहरण-रेप केस में थाने में वसूली महिला विवेचक निलंबित

पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद शिकायत पर पहली कार्रवाई

रायपुर। गंज थाना क्षेत्र में छोटा-मोटा कारोबार करने वालों से मारपीट और अवैध वसूली की शिकायत करने महिला-पुरुषों की भीड़ गंज थाने पहुंच गई। वहां पदस्थ सिपाही केशव सिन्हा पर वसूली के आरोप लगाए गए। कारोबारियों से गाली-गलौज, सामानों को जब्त करने और लॉकअप में बंद करके छोड़ने के नाम पर वसूली के आरोप लगाए गए। मामले की शिकायत पुलिस कमिश्नर तक पहुंचने पर सिपाही को लाइन अटैच करने के आदेश दिए गए हैं। एडिशनल डीसीपी ने सिपाही को थाने से हटाने जाने की पुष्टि की है। वेस्ट पुलिस कमिश्नरी रायपुर के डीसीपी संदीप पटेल ने कबीरनगर थाने में पदस्थ एक महिला प्रधान आरक्षक को लेन-देन की शिकायत पर निलंबित कर दिया है। आरोप है कि चंद्रकला साहू नामक महिला विवेचक ने नाबालिग के अपहरण और रेप केस में जेल भेजे गए। आरोपी के पक्ष से लेन-देन करके पीड़ित पक्ष को परेशान किया। इसकी शिकायत मिलने पर जांच शुरू कर दी गई है। जबकि प्रथम दृष्यटया आरोप को सही मानते हुए प्रधान आरक्षक को निलंबित करने के साथ ही लाइन अटैच कर दिया गया है। कमिश्नरी लागू होने के बाद निलंबन और लाइन अटैच की यह पहली कार्रवाई है। डीसीपी वेस्ट संदीप पटेल ने निलंबन आदेश जारी करते हुए कहा है कि धारा 137 (2) 67, 64 (2) बीएनएस एवं 4, 6 पास्को एक्ट के प्रकरण की विवेचना में विवेचक प्रधान आरक्षक क्रमांक 1507 चंद्रकला साहू द्वारा स्वेच्छाधारिता एवं संदिग्ध आचरण प्रदर्शित किया गया। इसके फलस्वरूप उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर रक्षित केन्द्र संबद्ध किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ऐसा कृत्य

थाने में दर्ज 16-17 वर्षीय नाबालिग के अपहरण के केस की जांच में रेप का मामला सामने आया। आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। शिकायत मिली कि महिला जांच अधिकारी ने पीड़िता का कथन लेने के दौरान आरोपी का फेवर किया। लेन-देन के आरोप भी लगाए गए हैं। निलंबन करके जांच के आदेश दिए गए। इस तरह का कृत्य और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

- संदीप पटेल डीसीपी वेस्ट रायपुर

दो घूसखोर अफसरों को 3-3 साल कठोर सजा

50-50 हजार जुर्माना भरने का भी आदेश, अभनपुर नगर पंचायत का मामला

रायपुर। ठेका के बदले रिश्वत लेने वाले दो अधिकारियों के खिलाफ विशेष न्यायाधीश ने बड़ा फैसला सुनाया है। छह साल बाद आरोप सिद्ध होने पर दोनों आरोपियों को तीन-तीन साल कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त छह-छह माह कठोर सजा का प्रावधान है।

यह मामला अभनपुर नगर पंचायत का है। इस मामले में अंतिम सुनवाई 31 जनवरी, शनिवार को विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) मधुसूदन चंद्राकर की कोर्ट में पूर्ण हुई। इस मामले की पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक विपुल नायक ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्त सब इंजीनियर नगर पंचायत अभनपुर सुरेश गुप्ता और सीएमओ नगर पंचायत अभनपुर अनिल शर्मा ने पद का दुरुपयोग करते हुए ठेका देने के नाम पर रिश्वत की मांग की थी, जिसे एन्टी करप्शन ब्यूरो रायपुर ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। पीड़ित जय प्रकाश गिलहरे ने 22 दिसंबर 2018 को इसकी लिखित शिकायत की थी। शिकायत में बताया कि जेपी कन्स्ट्रक्शन का प्रोपराइटर है, जो द वर्ग ठेकेदारी के लिए पंजीकृत है। नगर पंचायत अभनपुर में पुष्प वाटिका निर्माण कार्य के लिए 55,55,000 रुपए का ठेका सितंबर 2017 में लिया था। निर्माण कार्य के लिए प्रथम किस्त 19,66000 रुपए का भुगतान हुआ। उसी समय 10 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी अनिल शर्मा ने लिये। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद शेष राशि 33,85,000 रुपए के लिए जब अनिल शर्मा से सम्पर्क किया तो उन्होंने फिर से स्वयं और अध्यक्ष के नाम पर 4 लाख रुपए रिश्वत की मांग की। पीड़ित ने रिश्वत न देने का मन बनाते हुए जब शिकायत की तो 31 दिसंबर 2018 को एंटी करप्शन ब्यूरो, रायपुर ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

पुलिस कमिश्नरी कोर्ट 15 से, मिला प्रशिक्षण

पुलिस अधिकारियों के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के दायित्वों पर 2 दिनी प्रशिक्षण संपन्न

रायपुर। 23 जनवरी से रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के पश्चात कमिश्नरेट के अंतर्गत कार्यरत सहायक पुलिस आयुक्त से उच्च श्रेणी के अधिकारियों के लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के कायारों से संबंधित एक दो दिवसीय विशेष पाठशाला/ प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। 30 एवं 31 जनवरी को हुई कार्यशाला में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के अंतर्गत पुलिस अधिकारियों को प्रदत्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट संबंधी अधिकारों, दायित्वों, कानूनी प्रावधानों तथा व्यावहारिक प्रक्रियाओं की गहन समझ प्रदान की गई, ताकि कानून-व्यवस्था एवं प्रशासनिक कायारों का त्वरित, प्रभावी एवं विधिसम्मत निर्वहन सुनिश्चित किया जा सके। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने चर्चा में कहा कि 15 फरवरी से कमिश्नरी कोर्ट प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसकी तैयारियां जल्द पूरी कर ली जाएंगी।

आम लोगों का विश्वास और मजबूत होगा : पुलिस कमिश्नर

प्रशिक्षण सत्र के उद्घाटन सत्र में डॉ संजीव शुक्ला ने कहा कि पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली की उपयोगिता तथा इसके अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का उपयोग सजगता एवं प्रभावी ढंग से किया जाना आवश्यक है।

जिससे आमजनों का पुलिस पर विश्वास और अधिक मजबूत हो तथा क्षेत्र में असामाजिक तत्वों एवं बदमाशों के हौसले पस्त हों। पूरे प्रशिक्षण सत्र के दौरान अमित तुकाराम कांबले (एडीशनल सीपी), उमेश गुप्ता डीसीपी मध्य जोन, मयंक गुर्जर डीसीपी उत्तर जोन, संदीप पटेल डीसीपी पश्चिम जोन तथा स्मृतिक राजनाला डीसीपी साइबर एवं क्राइम उपस्थित रहे। प्रमुख प्रशिक्षक के रूप में के. के. वाजपेयी द्वारा अधिकारियों को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के दायित्वों, वैधानिक शक्तियों एवं प्रक्रियात्मक पहलुओं पर विस्तृत एवं व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इस दौरान सभी एडीशनल डीसीपी, एसीपी अपने कार्यपालिक स्टाफ के साथ उपस्थित रहे।

नारा लगाने वालों की स्मृतियों को संजोने गांव का नाम हुआ नारागांव

डा. प्रकाश पतंगीवार

नारागांव के सुकालू, पीताम्बर, बिसाहू और सूरजू भी शामिल थे। इन चारों सेनानियों ने 19 अक्टूबर 1930 को जिला स्तर पर जल सत्याग्रह में भाग लिया था। इसी तर्ज पर सिहावा, रुद्री, नवागांव और कंडेल में भी सत्याग्रह हुआ। चारों सैनिक 24 दिन जेल में रहे। 24 नवम्बर 1930 को इन्हें जेल से छोड़ा गया। जेल से छूटने के बाद इन्होंने आंदोलन को जारी रखा।

जब महात्मा गांधी दूसरी बार धमतरी आए तो गुरूर अंचल के किसानों के साथ नारागांव के निवासी भी आंदोलन में भाग लेने गए थे। तब भीड को तितर बितर करने के लिए अंग्रेजों ने दमन चक्र चलाया। जब अत्याचार किया जाने लगा तब आसपास के गांव के नौजवान उत्तेजित हो गए और अंग्रेजों के विरुद्ध नारे लगाते रहे। बहुत से किसानों को जेल भेज दिया गया। इसमें नारागांव के सुकालू, पीताम्बर, बिसाहू और सूरजू भी शामिल थे। इन चारों सेनानियों ने 19 अक्टूबर 1930 को जिला स्तर पर जल सत्याग्रह में भाग लिया था। इसी तर्ज पर सिहावा, रुद्री, नवागांव और कंडेल में भी सत्याग्रह हुआ। चारों सैनिक 24 दिन जेल में रहे। 24 नवम्बर 1930 को इन्हें जेल से छोड़ा गया। जेल से छूटने के बाद इन्होंने आंदोलन को जारी रखा।

क्षेत्र के गांव गांव जाकर आजादी की अलख जगाई। यहां के निवासियों ने खूब यातनाएं सही। सिंचाई की सुविधा उस समय उपलब्ध नहीं थी। खेती किसानी के लिए पानी जरूरत होने पर उपलब्ध नहीं कराई जाती थी। आज नारा लगाने वाले सेनानी सदा के लिए देश हित में नारा लगाते अमर हो गए। गांव के लोगों ने उन सेनानियों की स्मृतियों को संजोने गांव का नाम नारागांव रख दिया। एक तरह से उन स्वतंत्रता सेनानियों के समर्पण, त्याग और बलिदान को चिर स्थाई बनाए रखने के लिए लिया गया ऐतिहासिक कदम है।

अनोखी छटा बिखेरता
अंधियारझोला जलप्रपात

डी पी देशमुख

छत्तीसगढ़ का गरियाबंद जिला भी प्रकृति की नैसर्गिक सुंदरता को संजोए हुए हैं। आज भी यहां के जंगलों में सघन वनों के अलावा, अनेक दुर्लभ जीव जंतु के अलावा पर्वत पहाड़ों का भी अपना महत्व है। इसी तरह का अनेक विशेषताओं से भरा अंधियारझोला जलप्रपात है जो गरियाबंद से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ग्राम रसेला के समीप मलेवा मुड़ीपानी पहाड़ पर अपनी छटा बिखेर रही है। करीब 100 से 130 फीट ऊंचे पहाड़ से कल कल ध्वनि से गिरता जल अत्यंत मनमोहक होता है। यहां वर्ष भर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। पर्यटकों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। इस प्राकृतिक दृश्य तक पहुंचने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना लोगों को करना पड़ता है फिर भी इसका महत्व बढ़ता ही जा रहा है। ख़ासकर बरसात के दिनों में यहां का नजारा और भी खूबसूरत होता है।

आजादी का अलख जगाने का सशक्त माध्यम लोक नाट्य

डा. संतराम देशमुख

रामचंद्र देशमुख ने छत्तीसगढ़ देहाती कला विकास मंडल के माध्यम से आजादी का अलख जगाने अनेक लोक नाट्य का मंचन कर लोगों को देश की आजादी के प्रेरणाश्रोत के रूप में प्रदर्शन करते रहे, जिसमें काली माटी, बंगाल का अकाल, सरग अऊ नरक, जनम अऊ मरन, मिस मीयो का डांस और बेगुनाहों को फांसी प्रमुख रहे। नाचा के अंतर्गत प्रदर्शित इन प्रहसनो का उद्देश्य लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत करना ही था। यही नहीं, उस दिनों हास्य व्यंग्य युक्त कामेडी भी प्रस्तुत की जाती थी। जिसके नायक अक्सर अंग्रेजी शासन की जी हुजूरी करने वाले थैली शाह हुआ करते थे, मसलन राय साहब मिस्टर भोंदू। इन लोक नाट्य का गहरा असर लोगो पर दिखने लगा, जिससे कलाकारों का उत्साह बढ़ने के कारण अनेक स्थानों पर लगातार मंचन होते रहती थी। पहले के लोग आज भी इन प्रस्तुतियों को याद कर भावुक हो जाते हैं।

आस्था से जुड़ा होता है बेलपान मेला

प्रो. अश्विनी केशरवानी

छत्तीसगढ़ अंचल में फाल्गुन मास तक मेला मड़ई का दौरा चलता है। प्राचीन काल से ग्रामीण अंचलों में मेला मड़ई का आयोजन होता आ रहा है जिसमें ग्रामीण खेती किसानी के कार्यों से निवृत्त होने के बाद मनोरंजन के लिए यह आयोजन करते आ रहे हैं। इस मेला मड़ई के स्वरूप में आधुनिकता का समावेश होना स्वाभाविक पर लोगों का रुझान आज भी देखी जाती है।

मेला अक्सर विशेष अवसरों पर खासकर नदी के किनारे आयोजित होते हैं जिसमें लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी होती है। ऐसे ही धार्मिक महत्व का मेला बिलासपुर जिला मुख्यालय से 30 कि मी और तखतपुर से 12 कि मी की दूरी पर बेलपान स्थित है। यहां शिवजी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यहां एक कुंड से छोटी नर्मदा नदी का उदगम हुआ माना जाता है जो आगे जाकर मनियारी नदी में मिल जाती है। इस नदी में अस्थि विसर्जित की जाती है। यहां के शिव मंदिर का निर्माण सन 1757 से 1786 के बीच बिम्बाजी भोंसले ने कराया। इस स्थल पर प्रति वर्ष माघ पूर्णिमा को सात दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें दूर दूर से मेले में आकर अपनी आस्था प्रकट करते हैं।

कायदा+कानून=हद पार

नियमों की अनदेखी और भेदभाव का आरोप

प्रति,

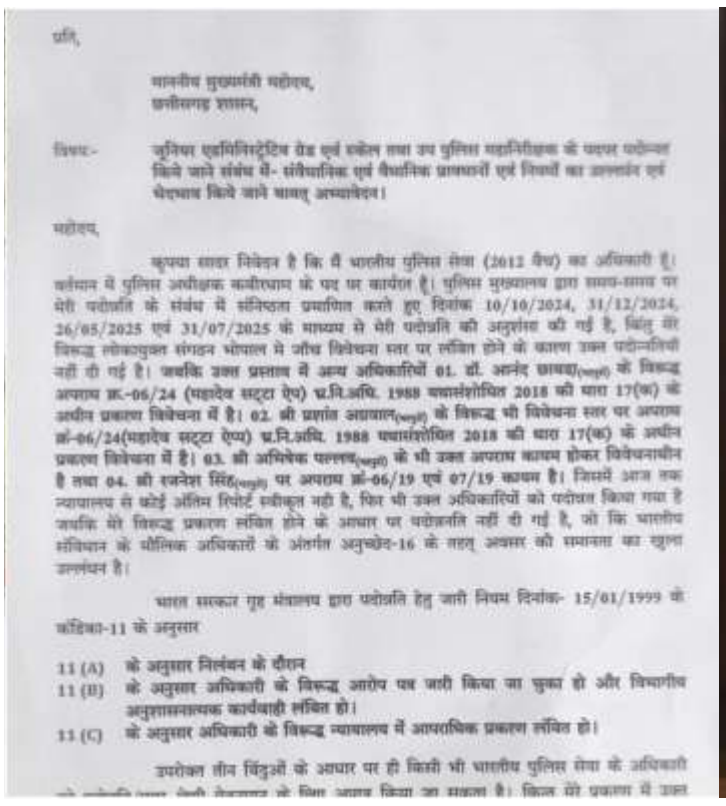

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
छत्तीसगढ़ शासन,

विषय:- जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड एवं स्केल तथा उप पुलिस महानिरीक्षक के पदपर पदोन्नत किये जाने संबंध में- संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधानों एवं नियमों का उल्लंघन एवं भेदभाव किये जाने बाबत् अभ्यावेदन।

महोदय,

कृपया सादर निवेदन है कि मैं भारतीय पुलिस सेवा (2012 बैच) का अधिकारी हूँ। वर्तमान में पुलिस अधीक्षक कबीरधाम के पद पर कार्यरत हूँ। पुलिस मुख्यालय द्वारा समय-समय पर मेरी पदोन्नति के संबंध में सत्यनिष्ठा प्रमाणित करते हुए दिनांक 10/10/2024, 31/12/2024, 26/05/2025 एवं 31/07/2025 के माध्यम से मेरी पदोन्नति की अनुशंसा की गई है, किंतु मेरे विरुद्ध लोकायुक्त संगठन भोपाल में जाँच विवेचना स्तर पर लंबित होने के कारण उक्त पदोन्नतियाँ नहीं दी गई है। जबकि उक्त प्रस्ताव में अन्य अधिकारियों 01. डॉ. आनंद छाबड़ा के विरुद्ध अपराध क्र.-06/24 (महादेव सट्टा ऐप) भ्र.नि.अधि. 1988 यथासंशोधित 2018 की धारा 17(क) के अधीन प्रकरण विवेचना में है। 02. श्री प्रशांत अग्रवाल के विरुद्ध भी विवेचना स्तर पर अपराध क्रं-06/24(महादेव सट्टा ऐप्प) भ्र.नि.अधि. 1988 यथासंशोधित 2018 की धारा 17(क) के अधीन प्रकरण विवेचना में है। 03. श्री अभिषेक पल्लव के भी उक्त अपराध कायम होकर विवेचनाधीन है तथा 04. श्री रजनेश सिंह पर अपराध क्रं-06/19 एवं 07/19 कायम है। जिसमें आज तक न्यायालय से कोई अंतिम रिपोर्ट स्वीकृत नही है, फिर भी उक्त अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है जबकि मेरे विरुद्ध प्रकरण लंबित होने के आधार पर पदोन्नति नहीं दी गई है, जो कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद-16 के तहत् अवसर की समानता का खुला उल्लंघन है।

भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा पदोन्नति हेतु जारी नियम दिनांक- 15/01/1999 के कंडिका-11 के अनुसार

11 (A) के अनुसार निलंबन के दौरान
11 (B) के अनुसार अधिकारी के विरुद्ध आरोप पत्र जारी किया जा चुका हो और विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित हो।
11 (C) के अनुसार अधिकारी के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक प्रकरण लंबित हो।

उपरोक्त तीन बिंदुओं के आधार पर ही किसी भी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी ...

विशेष संवाददाता/शेख आबिद
मोबाईल नंबर 8109802829

देश के किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ होगा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के एसपी धर्मेंद्र छवई ने प्रमोशन में नाइंसाफी को लेकर सीधे मुख्यमंत्री और डीजीपी को पत्र लिख डाला। पत्र का लहज़ा भी साधारण नही है। सुबाई सरकार से उनके खत में नाराजगी और गंभीर आरोपों के साथ खरा-खरा सवाल भी है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या एसपी सीधे मुख्यमंत्री को पत्र लिख सकता है? अगर नौकरशाह ही सरकार को निशाने पर लेने तो फिर उस राज्य के सिस्टम का क्या होगा? बड़ा सवाल यह भी है कि एसपी ने अगर सीमाएं लांघी तो सिस्टम ने क्या किया?

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे में पदोन्नति को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। भारतीय पुलिस सेवा (IPS) 2012 बैच के एक पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह छवई ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपने साथ हुए कथित अन्याय, भेदभाव और संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन की पीड़ा व्यक्त की है। पत्र में अधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नियमों के बावजूद उन्हें जानबूझकर पदोन्नति से वंचित किया गया।

पत्र के अनुसार, अधिकारी वर्तमान में कवर्धा पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं और पुलिस मुख्यालय द्वारा समय-समय पर जारी की गई पदोन्नति सूचियों (10 अक्टूबर 2024, 31 दिसंबर 2024, 26 मई 2025 और 31 जुलाई 2025) में उनके नाम पर विचार किया गया, लेकिन उन्हें पदोन्नत नहीं किया गया। इसका कारण बताया गया कि उनके विरुद्ध लोकायुक्त संगठन, भोपाल में जांच लंबित है।

अधिकारी ने अपने दर्द को शब्दों में बयां करते हुए लिखा है कि जिन अधिकारियों पर उनसे कहीं अधिक गंभीर आरोप हैं, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज हैं और जिन मामलों में न्यायालय से अंतिम रिपोर्ट तक नहीं आई है, उन्हें पदोन्नति का लाभ दे दिया गया। जबकि उनके मामले में न तो चार्जशीट जारी हुई है और न ही कोई विभागीय कार्यवाही लंबित है।

समान अवसर के नियमों का दिया हवाला

पत्र में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 15 जनवरी 1999 को जारी पदोन्नति नियमों का हवाला देते हुए बताया गया है कि यदि अधिकारी निलंबित नहीं है, आरोप पत्र जारी नहीं हुआ है और न्यायालय में आपराधिक मामला लंबित नहीं है, तो उसे पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद उन्हें वरिष्ठ वेतनमान और उप पुलिस महानिरीक्षक (DIG) के पद पर पदोन्नति नहीं दी गई। पुलिस अधीक्षक ने इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-16 के तहत समान अवसर के अधिकार का खुला उल्लंघन बताया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि समान परिस्थिति वाले अधिकारियों को पदोन्नत किया गया, जबकि उनके साथ भेदभाव किया गया, जिससे उनका मनोबल आहत हुआ है।

- **कबीरधाम एसपी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र**
- **पदोन्नति से वंचित होने का पैमाना छलक गया**

कटघरे में पदोन्नति प्रक्रिया-निष्पक्षता

25 साल में ऐसा कभी किसी डायरेक्ट आईपीएस अफसर ने भी नहीं किया। तेज़ तर्रार आईपीएस रहे मुकेश गुप्ता जैसे अब तक के सबसे दमदार अफसर की भी हिम्मत नहीं पड़ी। जबकि उन्हें भी तत्कालीन डीजीपी ओपी राठौर की वजह से डीआईजी से आईजी बनने के लिए कई साल वेट करना पड़ा था। अधिकारी के इस पत्र ने पुलिस विभाग में पदोन्नति प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री और राज्य सरकार इस संवेदनशील मामले में क्या कदम उठाती है और क्या एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को उसके अधिकार और सम्मान मिल पाता है या नहीं।

क्या सूबे के मुलाजिम हो गए हैं बेख़ौफ़ ?

कर्मचारियों की तुलना में बड़े अधिकारी ज्यादा अनुशासनहीनता कर रहे। जैसे पुलिस अधीक्षक कबीरधाम धर्मेंद्र छवई ने नियम-कायदों को ताक पर रख सरकार को पत्र लिख दिया। लगता है सूबे के मुलाजिम अब बेख़ौफ़ होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बेतरतीब होती अफसरशाही के लिए मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक भी जिम्मेदार हैं। इस घोर अनुशासनहीनता के लिए अब तक चिट्ठी-पत्री करने वाले अफसर को सीएस और डीजीपी ने तालाब तक नहीं किया है।

नाम, पैसा, शोहरत और दु:साहस

आईपीएस धर्मेंद्र छवई पर बैकडोर से आईपीएस बनने का आरोप लगा था। उन्होंने रापुसे अधिकारी के रूप में पूरी नौकरी एमपी में की थी। वहां एक संवेदनशील केस में सस्पेंड हुए, एफआईआर भी हुआ। एमपी से 18 साल बाद 2018 में छत्तीसगढ़ आए। और उन्होंने छत्तीसगढ़ के रापुसे अधिकारियों के विरोध के बाद भी आईपीएस बनकर दिखा दिया कि दमदार हैं। छवई अगर मध्य प्रदेश में होते तो इस साल आईपीएस बनते। बैच भी 2016 या 17 मिलता। छत्तीसगढ़ में वे 2023 में आईपीएस बने और बैच भी 2013 का मिल गया। एसपी के तौर पर बेमेतरा, महासमुंद के बाद कवर्धा उनका तीसरा जिला है। छत्तीसगढ़ में नाम, पैसा और शोहरत पाने के बाद भी सीधे सरकार से चिट्ठी-पटरी कर रहे हैं तो इससे साबित होता है कि वे कितने दु:साहसी पुलिस अधिकारी हैं।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक श्री सुकांत राजपूत द्वारा ए.आर. प्रिंटर्स, निरंकारी फर्नीचर के पीछे, पंडरी रायपुर से मुद्रित एवं शहरसत्ता, एस-15 प्रियदर्शिनी नगर, सेक्टर 1, मातृ-पितृ छाया अपार्टमेंट, रायपुर (छ.ग.), मोबाईल नं. 98271-81979, फोन नं. 0771-3158142, संपादक - सुकांत राजपूत (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार के लिए जिम्मेदार), महाप्रबंधक - प्रदीप चंद्रवंशी (मो. 70006-81023)। डाक पंजीयन - CG/RYP/DN/70/2025-27